SCHOOL LEADERSHIP ACADEMY JHARKHAND



School Leadership Development Program

MODULES

2022-2023

Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail:jcert.ran@gmail.com

SCHOOL LEADERSHIP ACADEMY JHARKHAND

School Leadership Development Program

MODULES

2022-2023

Jharkhand Council of Educational Research and Training, Ranchi
D.I.E.T Campus, Ratu, Ranchi-835222, e-mail:jcert.ran@gmail.com

प्राकथन

NCSL, NIEPA, नई दिल्ली के राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम के तहत झारखण्ड के विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए **JCERT** राँची के **SLA** के द्वारा यह मॉडयूल निर्मित किया गया है। प्रत्येक विद्यालय को एक उपयोगी शिक्षा संगठन में रूपांतरण के लिए स्थानीय संदर्भो को विशेष महत्ता दी गई है।

इस मॉडयूल के माध्यम से झारखण्ड से सम्बंधित मुद्दो पर सामाग्री तैयार की गई है। इन मुद्दों पर विद्यालय प्रधान समझ विकसित करेंगे और अपने विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। झारखण्ड राज्य की अपनी भौगोलिक स्थिति, परिवेश, सांस्कृतिक मूल्य, भाषा एवं क्षेत्र संबंधी मुद्दे एवं चुनौतियाँ हैं। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्मित सामग्री में झारखण्ड राज्य से जुड़े मुद्दों का भी समावेश किया जाए ताकि पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री की रूपरेखा को और समृद्ध एवं मूल्य परक बनाया जा सके। इस उद्देश्य से विद्यालय नेतृत्व संस्थान, झारखण्ड के अगुवाई में झारखण्ड के विभिन्न विद्यालयों के विद्यालय नेतृत्वकर्ता के विमर्शोपरांत झारखण्ड राज्य के संदर्भ में अलग–अलग मुद्दों को चयन कर मॉडयूल तैयार किया गया है। इस पुस्तिका में इसके उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में तैयार मॉडयूल विद्यालय नेतृत्वकर्ता के दायित्व निर्वहन में आने वाली चुनौतियों को सकारात्मक तरीके से निपटने में, उनके कौशल विकसित करने में मददगार सिद्ध होगा।

डा. डी. एन. सिंह

Modules Development Committee

Direction	Mr. K. Ravi Kumar, I.A.S. Secretary, Deparment of School Education and Literacy
Co-Direction	Ms. Kiran Kumari Pasi, I.A.S. Director, JCERT
Guidance and Monitoring	Mr. Pradip Kumar Chubey Deputy Director, JCERT Dinesh Upadhyay, Consultant Charu Malik, NCSL, New Delhi

Coordinator and Writer

Dr. D.N. Singh

School Leadership Academy, Jharkhand

Writers:

1.	Dr. Shahnawaz Quraishi	PGT, Govt. Girl's +2 High School, Bariatu, Ranchi
2.	Supriya Kumari	PGT, S.S. +2 High School, Bero, Ranchi
3.	Dr. Nirupama Kumari	TGT, Ramrudra +2 High School, Chas, Bokaro
4.	Amad Uddin Raghib	PRT, U.H.S Amlabad, Chandankiyari, Bokaro
5.	Anjani Anand	TGT, M.s. Ganeshpur, Balumath, Latehar
6.	Bhupesh Prasad Srivastava	PRT, G.M.S. Hindi Boys, Paharitola, Ranchi
7.	Tara Kumari	Principal (I/c), GM.S. Buti, Ranchi
8.	Betul Sudharm	Principal (I/c), G.M.S. Kanta Toli, Ranchi
9.	Regis Medline Bara	PRT, M.S. Bariatu, Ranchi
10.	Prabhat Ranjan Kumar Singh	PGT, Model School, Kanke, Ranchi
11.	Himanshu Kumar Deo	PRT, Primary School, Gopalpur, Deoghar

Graphics Designer

Md. Imran Khan

Graphics In Design: 7903996468

विषय–सूची

1.	कुपोषण	06–11
2.	मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी	12–20
2.	सड़क सुरक्षा	21–29
3.	छीजन की चुनौती	30–36
4.	दहेज प्रथा व उनके उन्मूलन	37–46
5.	सीखने के प्रतिफल	47–57
6.	झारखण्ड में बहुभाषिकता	58–63
7.	बाल विवाह	64–73
8.	सामाजिक भावनात्मक अधिगम	74–84

झारखण्ड के बच्चों में कुपोषण दूर करने में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका

+ 2 उच्च विद्यालय कुम्हरलालो, गिरिडीह

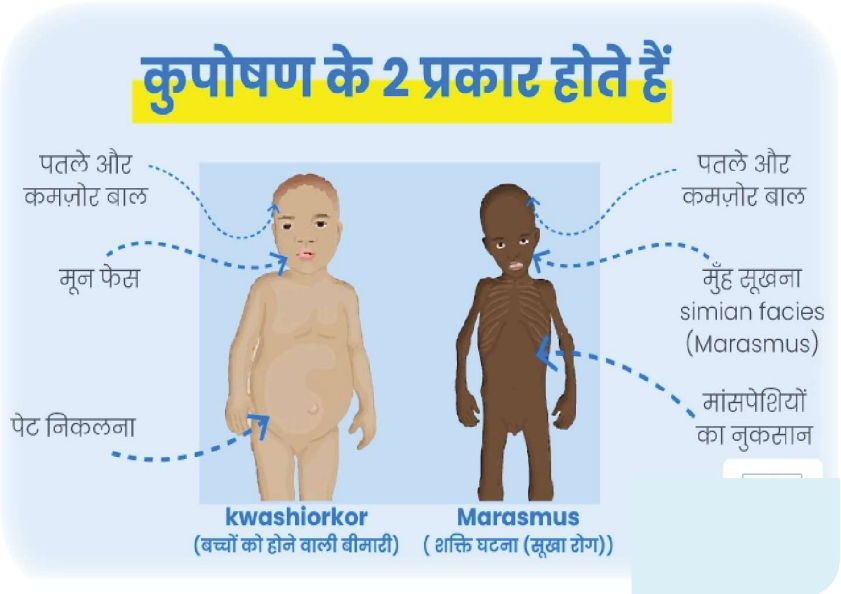


डॉ.डी.एन. सिंह

स्कूल लीडरशिप अकेडमी, झारखण्ड

कुपोषण

बालक कुपोषित तब कहा जाता है जब उसका विकास उसकी क्षमता के अनुसार नहीं होता अर्थात अपनी उम्र के अनुसार एक सामान्य और स्वस्थ बालक की तरह जो विकास होना चाहिए, उससे बालक वंचित रह जाता है। हालांकि पांच वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों में एक गति से बढ़ने की क्षमता होती है परन्तु एक समान उनका विकास नहीं हो पाता। समाज के लोगों में कुपोषण के दुष्परिणाम की जानकारी नहीं होती है। बालक के कुपोषित होने का अर्थ है कि उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास की प्रक्रिया जीवन भर के लिए बाधित हो जाती है। शरीर के लिए आवश्यक सन्तुलित आहार लम्बे अवधि तक नहीं मिलना ही कुपोषण है।



लक्षण

यह प्रायः तब होता है जब बीमारी की वजह से बालक का वजन घट जाता है। यदि बीमारी का चिकित्सा हो जाये और बालक को पर्याप्त भोजन मिले तो खोया हुआ वजन दोबारा मिल सकता है परन्तु यदि बालक को पर्याप्त भोजन नहीं दिया गया तो उसका शरीर और दिमाग विकसित नहीं हो पायेगा। अत्यधिक दुबले व कम वजन वाले बालक गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है।

कारण

शारीर में पोषक तत्वों की कमी या अभाव मुख्यतः दो प्रकार से होता है जिसमें कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहला दोषयुक्त भोजन ग्रहण करने से अर्थात ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्वों के गुण तथा परिणाम का अभाव हो, उसे दोषयुक्त भोजन कह सकते हैं।

दूसरा अभावयुक्त भोजन के ग्रहण करने से भी कुपोषण हो जाता है। किन्ही परिस्थितियों में पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है तथा आहार द्वारा इस मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है

कुपोषण का सीधा संबंध हमारे समाज में व्याप्त रुढ़िवादी परम्पराओं से भी है। इस परम्परा से माँ और बच्चों को स्वस्थ रखने में बाधा बन रही है। कुपोषण का सीधा सम्बन्ध कुछ हद तक कुपोषित माँ से भी है। आम तौर पर हमारे समाज में देखा गया है कि परिवार के सभी सदस्यों को खिलाने के बाद माता स्वयं खाना खाती है। पहले उसका पति और बच्चे, फिर कहीं जाकर उसकी बारी आती है। आखिरी में उसे जो भोजन मिलता है वह उसके लिए पर्याप्त है या नहीं, यह कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करता।उस पर कोई ध्यान नहीं देता। सभी लोग एक साथ बैठ कर भोजन नहीं करते।

समाज की कुछ और परम्पराएं भी जिम्मेदार हैं। प्रायः देखा गया है कि जैसे–जैसे लड़की बड़ी होती है तो कई शारीरिक और सामाजिक बदलाव उसे माँ की तरफ आकर्षित करते हैं। अब लड़की भी अपनी माँ के साथ भोजन करने लगती है। अब माँ के साथ बेटी भी कुपोषण का शिकार होने लगती है। और यह चक्र इसी तरह चलता रहता है। आमतौर पर हमारे समाज में माँ के पोषण का ध्यान गर्भावस्था में ही दिया जाता है। किशोरियों में हर माह मासिक धर्म के दौरान रक्त स्राव होना भी कुपोषित होने का मुख्य कारण होता है।

कम उम्र में शादी भी कुपोषित होने का कारण बनता है।

बार बार प्रसव होने से माँ कुपोषित हो जाती है।

पुत्र की चाहत में माँ को बार बार प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कई बार महिलाओं के पास यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता कि वह कब गर्भवती हो। यह फैसला या तो उनका पति लेता है या सास। इसमें दो बच्चों के बीच में अंतर का भी ध्यान नहीं रखा जाता। जिसकी वजह से जन्म लेने वाले बच्चों के साथ–साथ माँ भी कुपोषण का शिकार हो जाती है।

प्रोटीन की न्यूनता बच्चे को कुपोषित कर देता है।

संतुलित भोजन के ज्ञान का अभाव, भोजन संबंधी गलत आदते, भोजन पकाने की उचित विधियों के ज्ञान का अभाव, भोज्य तत्वों के पोषक मूल्यों के ज्ञान का अभाव भी कुपोषण की ओर जाना स्वाभाविक है।

प्रकार

कुपोषण दो प्रकार के होते हैं कम (अल्प) पोषण (कम वजन, नाटापन, दुबलापन एवं सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी) एवं अधिक (अति) पोषण (अधिक वजन, मोटापा एवं पोषण से सम्बंधित दीर्घकालीन बीमारियाँ जैसे मधुमेह)

झारखण्ड में कम पोषण की समस्या से उत्पन्न कम वजन, नाटापन और दुबलापन है।

परिणाम

कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं।

★ उच्च रक्त चाप, मधुमेह, हृदय रोग एवं मोटापा जैसी बीमारियों से जूझना

★ शिक्षा देर से शुरू करना एवं बीच में ही छोड़ देना

★ कमजोर दिमाग एवं विलंबित मानसिक विकास के कारण सीखने की क्षमता में कमी

कम पोषित महिलाओं के छोटे और कम वजन वाले बच्चे पैदा करने की सम्भावना बनी रहती है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण और गरीबी का कुचक्र बना रहता है।

» कुपोषण जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत तक अपना दुष्प्रभाव दिखाता है।

» संक्रमण और बीमारी की अधिक सम्भावना

» मृत्यु का अधिक खतरा

» ज्ञान ग्रहण करने (Cognitive) की कमजोर क्षमता

» कमजोर विकासात्मक परिणाम

» जल्दी थक जाना

कुपोषण दूर करने में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका–

कई मायने में कुपोषण न केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि पुरे परिवार, समाज एवं राज्य को प्रभावित करता है। अच्छी खबर यह है कि जीवन के प्रथम 1000 दिन में (गर्भावस्था से लेकर बालक के 24 माह होने तक), महिला एवं बालक को पर्याप्त एवं उपयुक्त पोषक आहार देने से कुपोषण को रोका जा सकता।

पहला गर्भ धारण करने से पहले महिलाओं को पूरी तरह से पोषित होना होगा और आदर्शतः पहले बच्चे का जन्म कम से कम 21 वर्ष की उम्र के बाद ही होना उचित होगा।

सभी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विभिन्न प्रकार के भोजन खाने एवं गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से IFA की गोली खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी बालकों को जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर माँ का दूध देना चाहिए एवं छः माह (180 दिन) तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए तथा 24 महीनों तक माँ का दूध देते रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिशु को कोलस्ट्रम (पहला पीला गाढ़ा दूध) जरूर मिले जो कि शिशु का पहला टीका जैसा होता है।

छ माह (180 दिन) के होने पर शिशु को भी के दूध के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण ऊपरी आहार भी देना शुरू करना चाहिए एवं बढ़ती उम्र के साथ साथ भोजन की मात्रा एवं आवृत्ति भी बढ़नी चाहिए। भोजन में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए एवं जितना हो सके पशु जनित (पशु से मिलने वाला प्रोटीन) आहार भी भोजन में शामिल करना चाहिए।

खाना बनाने से पहले एवं शिशु को खिलाने से पहले माता तथा केयरटेकर को साबुन से हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए।

★ खुले में शौच करने की आदत को बंद करना चाहिए।

★ महिलाओं को दो गर्भावस्था के बीच सही खान–पान का ध्यान रखने एवं दो बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखना चाहिए।

कुपोषण को पहचानें का प्रयास करना चाहिए। इसकी प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को मिलना चाहिए। नाखून के पीले रंग देख कर भी कुपोषण को देखा जा सकता है।

रोटी, चावल, आलू, पास्ता, अनाज और अन्य स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थ दूध और डेयरी खाद्य पदार्थ जैसे पनीर और दही, मांस, मछली, अंडे, बीन्स, नट्स, और प्रोटीन के अन्य गैर डेयरी स्रोत सभी बच्चों को प्राप्त हो, इस बात से विद्यालय प्रधान अवगत हो। अपने शिक्षकों को भी बताएं कि बच्चों के स्वास्थ्य का अनुश्रवण लगातार करें।

एक कुपोषित माँ अवश्य ही एक कमजोर बच्चे को जन्म देती है, और कुपोषण चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस कुपोषण चक्र को तोड़ने में विद्यालय प्रधान की भूमिका अहम मानी जाती है।

जैसे एक मरा हुआ पौधा उचित देखभाल, पोषण जैसे मिट्टी पानी और धूप के बिना हरे भरे पेड़ में विकसित नहीं हो सकता, उसी तरह एक देखभाल और पोषण के बगैर स्वस्थ व्यस्क के रूप में विकसित नहीं हो सकता। एक बार बन जाने के बाद जिस तरह से खराब बने मिट्टी के घड़े को पुनः मिट्टी द्वारा

ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह अपने जीवन की शुरूआत में कुपोषण का शिकार हो जाने वालें बच्चों को पूरी तरह आदर्श रूप में स्वस्थ नहीं किया जा सकता।

यदि पोषण और कुपोषण के बारे में लोगो में जागरूकता आ जाए और परम्पराओं और रुढ़िवादिता का चक्र टूट जाए तो काफी हद तक कुपोषण को रोका जा सकता है। समुदाय में लड़का लड़की में होने वाले भेदभाव के प्रति हर व्यक्ति के सोच में बदलाव लाने पर ही कुपोषण को हराया जा सकता। इस जागरूकता को बढ़ाने में विद्यालय नेतृत्व काफी काम कर सकता है।

विद्यालय नेतृत्व निम्न उपाय से कुपोषण से निजात दिलाने में मददगार हो सकता है।

1 कुछ अंतराल पर बच्चों के कुपोषण की जाँच की जाए।

2 आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ नियमित दी जाए।

3 एलबेन्डाजोल की गोली निर्धारित समय अंतराल में बच्चों को दी जाए।

4 मध्याह्न भोजन में पोषक मूल्य को ठीक से परखा जाए।

5 कुपोषित बच्चों के अभिभावकों से लगातार संपर्क में रहने की सलाह अपने शिक्षकों को दी जाए।

6 कुपोषित बच्चों का वजन एवं उँचाई का डाटा बेस तैयार किया जाए।

7 कुपोषित बच्चों के लगातार निगरानी की जाए।

8 कुपोषण सेंटर के साथ नेटवर्किंग की जाए।

9 कुपोषण पर एक्सपर्ट से ब्याख्यान दिलवाना।

10 कुपोषण पर पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित करना।

11 कुपोषण पर नुक्कड़ नाटक करवाना।

12 कुपोषण पर आधारित विडियो फिल्म दिखाना।

13 कुपोषण से सम्बंधित रैली निकलवाना।

14 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, विटामिन, आदि के विषय में जानकारी हेतू कार्यशाला का आयोजन करना।

15 डाइट चार्ट बनवाने में मदद करना

16 हेल्थ चेक अप रिकार्ड बनवाना और उसको अपडेट करते रहना।

15 विद्यालय के वेबसाइट पर हेल्थ चेक अप रिकार्ड को अपलोड करना।

16 पोषण शिक्षा की ब्यवस्था करना।

17 यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल कर कुपोषण पर कार्यशाला चलाना।

प्रश्न :

1 कुपोषण से आप क्या समझते हैं?

2 कुपोषण के कौन कौन लक्षण दिखते हैं?

3 बच्चों में कुपोषण के कौन कौन कारण होते हैं?

4 कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं?

5 कुपोषण दूर करने में विद्यालय नेतृत्व के पाँच भूमिका बताएं?

मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी की रोकथाम में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका



श्रीमती सुप्रिया कुमारी (PGT एस0एस0 +2 बेड़ो, राँची)
डॉ0 शाहनवाज कुरैशी (PGT रा0बा0 +2 उच्च वि0 बरियातु, राँची)



प्रस्तावना

झारखण्ड, भारत के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है जिसमें मुख्य रूप से वन एवं खनिज सम्पदा सम्मिलित है। इसके साथ ही झारखण्ड राज्य आदिवासी बहुल अग्रणी राज्यों में से एक है। नए राज्य के गठन के बाद से, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा के प्रसार के लिए कई परियोजनाओं को लागू कर रहा है।



राज्य सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है लेकिन स्कूलों मे बच्चों के शत–प्रतिशत नामांकन और ठहराव का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। अभी भी ऐसी कई समस्याएँ समाज मे व्याप्त हैं जो कई रूपों में विद्यालय क्रिया कलाप छात्र उपस्थित, अधिगम प्रतिफल एवं छीजन को प्रभावित करते हैं जिसमे से मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी प्रमुख हैं।

उद्देश्य

1. मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी को समझना।
2. मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी की समस्या के निराकरण मे विद्यालय नेतृत्व की भूमिका को समझना।

गतिविधि :–1

बच्चों को कहानी के माध्यम से मानव तस्करी का अर्थ समझाएँ

कहानी :–1 बिरसमुनी गुमला जिले के भरनो प्रखंड के परसा गाँव की निवासी है और प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा है। उसके परिवार में माता–पिता एव चार छोटे भाई–बहन हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। पिता दिहाड़ी मजदूर है और उसकी माता पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमार से ग्रसित है। पिता की आमदनी का अधिकांश भाग माता के इलाज में खर्च हो जाता है। पैसे की तंगी के कारण घर के अन्य खर्च बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। बिरसमुनी की दोस्त आशा ने उसे बताया कि उसके चाचा जरूरतमंदो को शहर में नौकरी दिलाने का काम करते हैं। बिरसमुनी अपनी हालात से परेशान होकर अपनी दोस्त के चाचा मंगरा से मिलने जाती है। मंगरा उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे शहर में बहुत अच्छी नौकरी दिला सकता है। नौकरी के एवज में उसे अच्छी मेहनताना और रहने खाने की सुविधा भी मिलेगी। इस पैसे से वह अपने घर के खर्चे में सहयोग कर पाएगी। अपने परिवार के मना करने के बाद भी वह मंगरा चाचा के साथ नौकरी करने के लिए शहर चली जाती है।

शुरुआती कुछ महीनों तक उसका संपर्क उसके परिवार से बना रहता है और वह नियमित रूप से अपने परिवार को पैसे भेजती है। अचानक कुछ समय बाद उसका संपर्क परिवार से टूट जाता है। अब वह कहाँ और किस हालत में है उसकी कोई भी सूचना परिवार को नहीं मिल पा रही है। संपर्क करने पर उसका मोबाइल बंद आता है।

चर्चा के प्रश्न :–

- ★ बिरसमुनी को शहर क्यों जाना पड़ा?
- ★ मंगरा चाचा ने बिरसमुनी को क्या प्रलोभन दिया?
- ★ क्या परिवार के विरुद्ध जाकर बिरसमुनी का शहर जाने का निर्णय सही था?
- ★ क्या मंगरा चाचा जरूरतमंदों का सच में हितैषी था?
- ★ कुछ माह के उपरांत बिरसमुनी का संपर्क परिवार से क्यों टूट गया?

- ★ अब शिक्षार्थियों से यह पूछें कि क्या उन्होंने बिरसमुनी के साथ घटी घटना की तरह किसी अन्य घटना के बारे सुना है या उसके आसपास ऐसी घटना घटी है ?
- ★ क्या मंगरा चाचा की तरह ही कोई व्यक्ति उनके आस पास रहता है जो लड़कों, लड़कियों या महिलाओं को प्रलोभन देकर शहर ले जाता है?
- ★ बिरसमुनी के साथ जो घटना घटी उसे क्या कहा जाता है?

परिभाषा

"मानव तस्करी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत एक अपराध है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्यों को व्यापार है। जिसमें मुख्य रूप से बलपूर्वक तरीकों से शोषण के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका हस्तानांतरण, देह व्यापार, गुलामी, मानव अंगों का व्यापार आदि गैर कानूनी गतिविधियाँ सम्मिलित है।"
मानव तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए अपराधी को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

झारखंड में मानव तस्करी की स्थिति

मानव तस्करी भारत देश की एक गंभीर समस्या है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड भी सम्मिलित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में मानव तस्करी के 81.36% मामले 10 राज्यों से सामने आए, जिसमे झारखण्ड भी सम्मिलित है। जिसमें से 4.2% घटनाएँ झारखण्ड राज्य से हैं। आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी में जान पहचान का व्यक्ति, रिश्तेदार, मित्र आदि सम्मिलित रहते हैं।

SEPT-18 INDIAN EXPRESS

13 Jharkhand kids rescued from traffickers, four held

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI | SEPTEMBER 17

THE Delhi crime branch police arrested four persons including a woman for allegedly trafficking children from Jharkhand to the Capital. Thirteen minors, including 12 girls and a boy, were rescued with the help of Shakti Vahini, an NGO on whose complaint investigations into the matter began.

The police are investigating whether the traffickers had an intention to make the children work as domestic helps in Delhi and NCR or whether they were to be forced into the flesh trade. Police received a complaint from the NGO on Friday evening that children who were being trafficked from Jharkhand to Delhi would arrive by the Jharkhand Sampark Kranti Express train.

"We deployed our teams at the New Delhi Railway Station. The train reached around 9.30 pm and the children were identified and rescued," said Additional Deputy Commissioner of Police (Crime) P S Kushwaha. Police then arrested four persons who allegedly lured the children to the Capital.

"The accused Sunita Devi, 25, Manish Munda, 25, Sanjay Bah, 30 and Munna Munda, 35 are all natives of Jharkhand. We are verifying their antecedents with the local police," said Kushwaha.

The children have been sent to child shelters, police said. "At present, the children are not in a position to tell us why they were brought to Delhi," said a senior police officer, adding that police was contacting their parents. "We are yet to ascertain whether or not the parents were aware that their children were being brought to Delhi," said the officer.

सारणी – 1

क्र. स.	वर्ष	मानव तस्करी के दर्ज मामले
01	2018	373
02	2019	177
03	2020	140
04	2021	92

स्रोत – NCRB

» गतिविधि–2

शिक्षार्थियों के द्वारा मानव तस्करी से संबंधित एक नाटक का मंचन कराया जाए जिसमें मानव तस्करी के विभिन्न तरीके एवं उसके परिणाम को दर्शाया जाए।

सारणी – 2

मानव तस्करी के विभिन्न तरीके	मानव तस्करी के परिणाम / उद्देश्य
» प्रलोभन द्वारा » अपरहण द्वारा » बल प्रयोग द्वारा » धमकी द्वारा » भुगतान या किसी प्रकार का लाभ देकर » भर्ती के द्वारा » हस्तांतरण द्वारा » क्रय–विक्रय द्वारा	» बेगारी कराना » गुलामी के उद्देश्य से » सेवा के लिए विवश करना » देह व्यापार » यौन शोषण » शरीर के अंगों का व्यापार » जबरन विवाह इत्यादि।

» गतिविधि का प्रतिफल

» नाटक के मंचन द्वारा शिक्षार्थियों के मध्य जीवंत संदेश का प्रसार।

» शिक्षार्थियों के बीच चर्चा कराएँ कि मानव तस्करी से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं?

» गतिविधि – 3

कहानी – 2

प्रिया बालिका उच्च विद्यालय, बरियातु में कक्षा 8वीं की छात्रा है। नामांकन के लगभग 1 महीने के पश्चात् से ही उसकी उपस्थिति अनियमित होने लगी। कभी–कभी वह लगातार हफ़्ते भर भी अनुपस्थित रहने लगी। वर्ग शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी के पश्चात् विद्यालय प्रधान ने प्रिया के माता–पिता से संपर्क किया एवं उन्हें विद्यालय बुलाया। बात–चीत के क्रम उसके माता–पिता ने जानकारी दी कि प्रिया मुहल्ले के दो घरों में झाड़ू–पोछा एवं बर्तन धोने का काम करने लगी है। उसके अभिभावक द्वारा बताया गया कि आर्थिक तंगी के कारण प्रिया को मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा है। आवश्यकता पड़ने पर वह दिहाड़ी मजदूर का काम भी करती है। विद्यालय प्रधान के द्वारा अभिभावकों को यह जानकारी दी गई कि बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के किसी बच्चे को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। यह कानूनन अपराध है। जानकारी मिलने के बाद प्रिया के माता–पिता ने आश्वासन दिया कि वे प्रिया को नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे।

चर्चा के प्रश्न

- ★ प्रिया नियमित रूप से विद्यालय क्यों नहीं जाती थी?
- ★ विद्यालय प्रधान ने प्रिया के अभिभावक को विद्यालय क्यों बुलाया?
- ★ विद्यालय प्रधान ने प्रिया के अभिभावक को क्या जानकारी दी?
- ★ क्या प्रिया बाल मजदूर है?

- ★ अब शिक्षार्थियों से यह पूछें कि क्या उन्होंने अपने आस–पास प्रिया की तरह किसी अन्य बच्चे को ऐसा कार्य करते देखा है ?
- ★ प्रिया की तरह काम करनेवाले ऐसे बच्चे, क्या नियमित रूप से विद्यालय जा पाते हैं?
- ★ क्या ऐसे बच्चों की समझ नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले बच्चों के समान है?

परिभाषा

बाल मजदूरीः— बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा करने पर दो वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

झारखण्ड में बाल मजदूरी की स्थिति

सरकार एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं के साझा प्रयासों के कारण बाल मजदूरों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बाल मजदूरो की कुल संख्या 1.26 करोड़ थी जिसमें झारखण्ड की भागीदारी 3.21 प्रतिशत थी।



10 वर्षों के पश्चात् 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या 1.26 करोड़ से घट कर 43.53 लाख हो गई। इसमें झारखण्ड की भागीदारी 2.09 लाख हो गई।

सारणी –3

क्र.	बाल श्रमिक	2001	2011
1	भारत	126,00,0000	43,53,000
2	झारखण्ड	40,72,00	90,990

स्रोत :— जनगणना 2001 एवं 2011

» गतिविधि –4

प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शिक्षार्थियों को बाल श्रम के विषय, कारण एवं परिणामों को समझाने का प्रयास किया जाए।

सारणी –4

बाल मजदूरी के कारण	बाल मजदूरी से उत्पवन्न समस्याएँ
★ गरीबी ★ बढ़ती जनसंख्या ★ खाद्य असुरक्षा ★ अशिक्षा ★ बेरोजगारी ★ माता–पिता की मृत्यू ★ विभिन्ना कानुनी प्रावधानो का सख्ती से लागू न होना ★ न्यूनतम मजदूरी	★ बच्चें शिक्षा से दूर हो जाते हैं। ★ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ★ बच्चों से दुर्व्यहार ★ विस्थापन एवं असुरक्षित प्रवासन ★ यौन शोषण ★ भिक्षावृति ★ मानव अंगों का व्यापार ★ अपराधों में बच्चों की संलिप्तता ★ नशे की लत ★ बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में बाधा

मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी की रोकथाम में विद्यालय नेतृत्व की भूमिकाः–

विद्यालय जाने वाले छात्र एवं छात्राएं मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी में संलिप्त अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य होते है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंध रखते है। आर्थिक आवश्यकता के करणवश कई बार ये विद्यार्थी मानव तस्करों के झांसे में आ जाते हैं। मानव तस्करी या बाल मजदूरी जैसे अपराध को रोकने में विद्यालय नेतृत्व की अहम भूमिका हो सकती है। निम्नलिखित सुझावों को अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन करते हुए विद्यालय नेतृत्वकर्ता मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी जैसे अपराध की रोकथाम में अग्रणी भूमिका निभा सकते है।

1. विद्यालय नेतृत्वकर्ता के द्वारा सभी वर्ग शिक्षकों को निर्देश दिया जाएगा कि लम्बी अवधि से वर्ग में अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूची तैयार करे और उसे विद्यालय नेतृत्वकर्त्ता को उपलब्ध कराएँ। विद्यालय नेतृत्वकर्ता अनिवार्य रूप से सूची का अवलोकन करे एवं ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उनकी अनुपस्थिति का कारण ज्ञात करने का प्रयास करे। यदि मानव तस्करी या बाल मजदूरी जैसी किसी घटना के घटित होने का आभास हो तो तत्काल नजदीकी थाना में उससे संबंधित सूचना देने का प्रयास करे।

2. विद्यालय नेतृत्वकर्ता के द्वारा अनिवार्य रूप से विद्यालय परामर्श दात्री समिति का गठन किया जाय। इस समति में सभी शिक्षकों का भागीदारी सुनिश्चित की जाए। समिति का यह दायित्व हो कि नियमित रूप से महीने के अंतिम शनिवार को परामर्श सभा का आयोजन करे एवं मानव तस्करी एवं बाल मजदूरी जैसी प्रमुख समस्याओं के कारण, अपराध के तरीके एवं उसके धातक परिणामों एवं उससे बचने के उपायों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें।

3. विद्यालय नेतृत्वकर्ता संबंधित मुद्दो पर विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता के प्रसार के लिए बाल संसद NSS एवं NCC को जिम्मेदारी प्रदान करेंगे।

4. विद्यालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) की सहायता से विद्यालय में निःशुल्क कानुनी परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रयास विद्यालय नेतृत्वकर्ता के द्वारा किया जाए।

5. विद्यालय नेतृत्वकर्ता नियमित रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों का आयोजन करें एवं इन मुद्दो को समिति के समक्ष प्रमुखता से रखे तथा इसके समाधान के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करे ।

6. विद्यालय नेतृत्वकर्ता के द्वारा मानव तस्करी से संबंधित तरीके एवं परिणामों तथा इस अपराध से संबंधित धाराओं एवं सहायता केंद्रो एवं संपर्क दूरभाष नम्बरों का प्रदर्शन विद्यालय में जगह–जगह पर अनिवार्य रूप से दीवार पेंटिंग, पोस्टर या फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा ।

- » पुलिस हेल्प लाईन –100
- » चाईल्डलाईन –1098
- » गुमशुदा बच्चों के लिए हेल्पलाईन– 18002002325
- » महिला हेल्पलाईन –09431700003 एवं 181
- » महिला एवं बाल इकाई–09771432145
- » मानव तस्करी विरोधी इकाई –18003456531
- » झारखण्ड राज्य महिला आयोग –0651 2401849
- » झारखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग –0651 2401181
- » ई– राहत –1967
- » झारखण्ड राजय बाल संरक्षण सोसाईटी –0651 3059999

7. विद्यालय नेतृत्वकर्ता द्वारा बाल मजदूरी (निषेध एव ंनियमन) अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों के प्रदर्शन विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग अथवा फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से अनिवार्य रूप से करेगे ।

बच्चे खुश, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने के पात्र हैं।

बाल श्रम पर रोकथाम के लिए संवैधानिक प्रावधान

★ अनुच्छेद 15 (3) – बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनो कानून बना सकती हैं।

★ अनुच्छेद 21 – 6–14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी

★ अनुच्छेद 23 – बच्चों को खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है।

★ अनुच्छेद 24 – किसी फैक्ट्री, खान अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्षो से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेद करता है।

बाल मजदूरी से जुडे अपराधों की सूचना एवं साहयता के लिए सम्पर्क नम्बर :–

★ pencil.gov.in
★ चाइल्ड हेल्पलाईन 1800 102 7222
★ बचपन बचाओं अभियान – complaints@bba.org.in
★ newdelhi @unicef.org
★ गुमशुदा बच्चों के लिए हेल्पलाईन – 18002002325
★ चाईल्ड लाईन –1098
★ झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण सोसाईटी – 0651.3059999
★ बाल अधिकरों के संरक्षण हेतु निर्मित गठित आयोग– 09939372800
★ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन – 011–47511111

मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. मानव तस्करी क्या है?
2. मानव तस्करी के संभावित उद्देश्य क्या है?
3. मानव तस्करी के अपराध में किन व्यक्तियों की संलिप्ता हो सकती है?
4. मानव तस्करी की संभावना प्रतीत होने पर क्या करना चाहिए ?
5. किन उपयों से मानव तस्करी से बचा जा सकता है?
6. बाल मजदूरी क्या है?
7. बाल मजदूरी के संभावित उदेश्य क्या है?
8. बाल मजदूरी से उबरने के लिए क्या करना चाहिए ?
9. झालसा क्या है?
10. चाईल्ड लाईन का संपर्क नम्बर क्या है?

सड़क सुरक्षा में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका



निरुपमा कुमारी (टी.जी.टी. राम रूद्र +2 उच्च विद्यालय चास, बोकारो)

अधिगम–प्रतिफल

» स्कूली विद्यार्थियों के सड़क सुरक्षा के संबंध में उन्मुखीकरण की आवश्यकता को समझ पाएँगे।

» सड़क सुरक्षा में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका को समझते हुए इसका क्रियान्वयन करने में सक्षम हो पाएँगे।

सीखने की अवधि– 3 घंटे

सड़क सुरक्षा क्या है ?

आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक मानवीय जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक सड़क उपयोगकर्ता है। वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को कम कर दिया है लेकिन इसने दूसरी ओर जीवन के जोखिम को बढ़ा दिया है। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।



भारत में ही हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं जो पूरी दुनिया में होने वाली कुल मृत्यु का 13 प्रतिशत है। अधिकांश दुर्घटनाओं में चालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्यादातर मामलों में दुर्घटनाएँ या तो लापरवाही के कारण होती हैं या सड़क उपयोगकर्ता की सड़क सुरक्षा जागरूकता

जिला सड़क सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 से मई 2022 तक कुल 29 महीनों में राँची जिले में कुल 1465 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 827 लोग घायल हुए, जबकि 1037 लोगों की जान चली गयी।

रिपोर्ट के अनुसार शहर के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सड़क हादसे ज्यादा हो रहे हैं।

की कमी के कारण होती हैं। इसलिए, सड़क सुरक्षा शिक्षा जीवित रहने के किसी भी अन्य बुनियादी कौशल की तरह ही आवश्यक है।

हमारा उद्देश्य वर्तमान और भावी सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच सुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा जानकारी प्रदान करना है और हर साल हमारी सड़कों पर मृतकों और घायल लोगों की संख्या को कम करना है।[1] यह भी ध्यातव्य है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और ग्रामीण ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी अलग है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का भी अभाव है। इसे ध्यान में रखते हुए विद्यालय नेतृत्व को अपने अनुसार गतिविधियों को ढालना होगा।

विद्यालय नेतृत्व की सड़क सुरक्षा में भूमिका

भारत में कुल आबादी का लगभग 38% स्कूली बच्चों के रूप में हैं। यह एक विशिष्ट मानव संसाधन है। इन बच्चों में लगभग तीन चौथाई आबादी को प्रभावित करने की क्षमता है। ऐसी स्थिति में यदि स्कूली नेतृत्व प्रभावी हो और उनमें जिम्मेदारी का भाव जाग्रत कर सके तो यह समाज के लिए उपयोगी होगा।

झारखंड सहित 4 राज्य में घायल से अधिक मरने वाले

चार राज्य मिजोरम, पंजाब, झारखंड और यूपी ऐसे राज्य हैं, जहां सड़क दुर्घटनाओं में घायलों से अधिक मरने वाले की संख्या है। अन्य राज्यों में सड़क दुर्घटना में मरने वाले से अधिक घायलों की संख्या है।

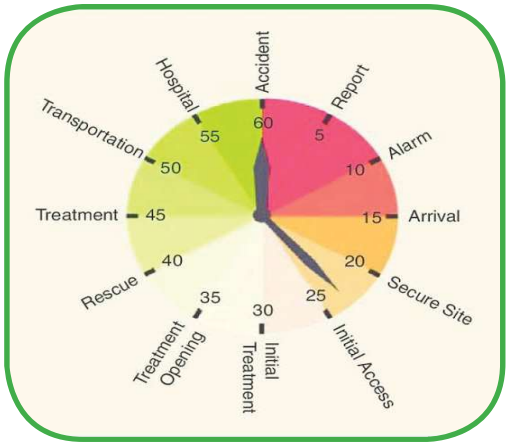
गुड सेमेरिटन

भारत बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं का दुर्भाग्यशाली शिकार है। देश में चार में से तीन लोग पुलिस उत्पीड़न, अस्पतालों में हिरासत और लंबी कानूनी औपचारिकताओं के डर से सड़कों पर घायल दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने से हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मदद करना चाहता है, तो ये कारक उसे ऐसा करने से रोकते हैं।

एक नेक समैरिटन एक ऐसा व्यक्ति है, जो नेकनीयती से, भुगतान या पुरस्कार की अपेक्षा के बिना और देखभाल या विशेष संबंध के किसी भी कर्तव्य के बिना स्वेच्छा से किसी दुर्घटना, या दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता या आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए आगे आता है, या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति, या आपातकालीन स्थिति में गुड सेमेरिटन कानून गुड सेमेरिटन को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर उत्पीड़न से बचाता है।

देश से लेकर प्रदेश तक में हर वर्ष हजारों लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम प्रयास के बावजूद सड़क दुर्घटना आज भी आम बात है। जिसको देखते हुए रांची के कोकर में रहने वाले ऋषभ आनंद ने रइज अप एनजीओ बना कर लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने का संकल्प लिया है। दिल्ली में पत्रकारिता की अच्छी खासी नौकरी छोड़ आज ऋषभ अपना पूरा समय सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान को दे रहे हैं। 14 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अमिताभ बच्चन एवं ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु के साथ ऋषभ आनंद ने भी स्टेज साझा किया। जहाँ अमिताभ बच्चन ने ऋषभ द्वारा रोड सेफ्टी पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की जमकर सराहना की. ड्रामा, कैंडल लाइट, कार्टून प्ले स्कूल, ब्लड डोनेशन, हेलमेट डिस्ट्रिब्यूशन, एग्जिबिशन आयोजित करा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं।

अगर हादसा होने के बाद अगले एक घंटे के अंदर मरीज को इलाज नहीं मिलता तो उसके बचने के अवसर काफी कम होने लगते है। इस समय काफी उम्मीद की जाती है। हादसे के बाद के पहले एक घंटे को गोल्डन ऑवर कहते है। एक अच्छे नागरिक के रूप में दुर्घटनाग्रस्त की सहायता करने में इस समय का ध्यान रखना आवश्यक है स इसके संबंध में भी विद्यार्थियों का उन्मुखीकरण आवश्यक है।



इस दृष्टि से सड़क–सुरक्षा में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विद्यालय नेतृत्व की भूमिका को हम तीन रूपों में देख सकते हैं :–

- जागरूकता
- सुनियोजित संगठन
- क्रियान्वयन

जागरूकता

वैसे तो पथ–परिवहन विभाग एवं सुरक्षा विभाग जागरुकता हेतु अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। 'सड़क–सुरक्षा सप्ताह' 11 जनवरी से 17 जनवरी तक विशेष रूप से जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लेकिन, यह विषय नियमित उत्प्रेरण की माँग करता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:–

प्राथमिक स्तर

★ रुको, इंतजार करो, चलो इसे खेल के माध्यम से सिखाया जा सकता है। इसमें बच्चों को 'हरा मतलव चलो, पीला मतलब तैयार हो जाओ, लाल मतलब रुको' बताने के बाद इन संकेत चिह्नों को किसी प्रकार दिखा कर कोई शारीरिक गतिविधि जैसे– दौड़ इत्यादि करवाई जा सकती है।



★ सड़क–सुरक्षा से संबंधित सामान्य–नियमों को गीत के माध्यम से बताया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा

बच्चों, सड़क पार जब करना,
इतनी बात ध्यान में रखना।
पहले अपने दाएँ देखो,
फिर से देखो दाएँ–बाएँ।
गर जो मोटर–गाड़ी आए।
हॉर्न, घंटी पड़े सुनाई,
रूक जाना तब मेरे भाई।
जब यह सड़क साफ दिख जाए,
मोटर–गाड़ी नजर न आए।
तभी संभल कर करना पार,
कहलाओगे तुम होशियार।

★ सड़क–सुरक्षा के सामान्य नियमों को दर्शाने के लिए स्कूल के गेट से कक्षा–कक्ष तक जाने वाले पाथ को या अन्य किसी भाग को ट्रैफिक पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसमें प्रमुख सड़क–सुरक्षा के चिह्नों को दर्शाया जाना चाहिए। इसके द्वारा बैगलेस डे (शनिवार) को इससे संबंधित कोई एक गतिविधि जैसे–ट्रैफिक पार्क या पथ में इसके नियमों से संबंधित खेल करवाए जा सकते हैं।



उच्च प्राथमिक स्तर

★ सड़क सुरक्षा से संबंधित सामान्य नियमों से संबंधित स्लोगन बनाना, रैली आयोजित करना जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती है।

इस तरह के फ्लैक्स या दीवार लेखन भी करवाए जा सकते हैं।

पैदल चलते समय ध्यान देने योग्य बातें	साईकिल से चलते समय ध्यान देने योग्य बातें	दो पहिया, चार पहिया/बस से चलते समय ध्यान देने योग्य बातें
★ पैदल चलने के दौरान हमेशा पैदल–पथ का उपयोग करें या किनारे होकर चलें। ★ सड़कों को पार करने के लिए जेब्रा क्रासिंग का उपयोग करेंस यदि यह उपलब्ध नहीं है तो सड़क को पार करते वक्त अतिरिक्त सतर्क रहें। ★ सड़कों को पार करते समय हमेशा पहले अपने बाईं ओर देखें, फिर दाएँ और फिर उसे पार करें। ★ जल्दी में सड़क पार न करें। ★ सड़क पर बाएँ तरफ ही पैदल चलें। ★ पैदल चलते समय मोबाईल का इस्तेमाल न करें। ★ पैदल चलने के दौरान कान में ईयर फोन के प्रयोग से बचें।	★ सुनिश्चित करें कि ब्रेक अच्छी तरह से काम कर रहा हो। ★ सड़क के बायीं ओर चलें या जहाँ भी संभव हो, सेवा–लेन का उपयोग करें। ★ बहुत तेजी से साईकिल न चलाएँ। ★ कोई स्टंट या कलाबाजी करने की कोशिश न करें। ★ व्यस्त सड़कों से बचें। ★ मोटर वाहनों से सुरक्षित दूरी रखें। ★ साईकिल पर अतिरिक्त वजन न लेकर चलें। ★ भारी वाहनों या चार पहिया वाहनों को ओवरटेक करने का प्रयास न करें। ★ साईकिल चलाने के दौराने कान में ईयर फोन के प्रयोग से बचें।	★ हमेशा सीट बेल्ट बाँधे। ★ हमेशा हेलमेट पहने। ★ चलती वहाँ के बाहर अपना सिर या शरीर का कोई हिस्सा न निकालें। ★ चलती बस के पीछे न लटकें। ★ सड़क पर साईकिल और मोटर साईकिल का रेस न लगाएँ। ★ वाहन चलाते समय फोन का उपयोग न करें। ★ नशा कर वाहन न चलाएँ। ★ वाहन चलाते समय फोन का उपयोग न करें। ★ वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। ★ वाहन चलाने के दौरान कान में ईयर फोन के प्रयोग से बचें।

☆ सड़क–सुरक्षा से संबंधित कविता लेखन, निबंध लेखन, चित्रांकन जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की जा सकती हैं।

☆ पाठ्य–पुस्तकों में भी इससे संबंधित कुछ अभ्यास हैं। इनसे संबंधित गतिविधियों को उस पाठ से जोड़कर भी किया जा सकता है। जैसे– JCERT कक्षा:7 की पाठ्यपुस्तक 'सामाजिक एवं राजनितिक व्यवस्था' का पाठ सं. 8 में दिए गए 'आईए चर्चा करें' भाग से चर्चा की जा सकती है।

☆ सड़क–सुरक्षा के चिह्नों से संबंधित चित्र या पोस्टर दीवारों पर लगवाया जा सकता है, जिससे आते–जाते अभिभावक, कर्मियों और विद्यार्थियों की उसपर नजर पड़े।

☆ भारत सरकार द्वारा तय नियमों को बताया जा सकता है एवं इससे संबंधित क्विज आयोजित किया जा सकता है। नीचे दिए गए QR Code को स्कैन कर आप क्विज के लिए प्रश्न देख सकते हैं।



☆ इससे संबंधित रोलप्ले जिसमें दुर्घटना उसके प्रभाव और नागरिक के रूप में भूमिका को दर्शाया जा सकता है। इस विषय पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा सकता है।



☆ लाइसेंस पाने की उम्र से पहले वाहन चलाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए दुर्घटनाओं से संबंधित चर्चा और उससे संबंधित निर्णय लेने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए नीचे दिए गए विडियो को दिखाकर या इसे कहानी के रूप में सुना कर विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जा सकती है

https//drive-google-com/file/d/1efhBKLgOS2HceOFLYEuj82YHfSNVGq3/view\usp¾sharing

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर

इस स्तर पर विद्यार्थी किशोरावस्था में होते हैं। उनमें नई चीजों को जानने और कर के देखने की जिज्ञासा चरम पर होती है। ऐसे में ट्रैफिक के नियमों को न जानना, कठिन परिस्थितियों में निर्णय न ले पाना, सुरक्षा उपायों को न अपनाना उनके लिए अधिक घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही, इस उम्र तक आते–आते वे किसी दुर्घटनाग्रस्त

व्यक्ति की सहायता करने में भी सक्षम हो जाते हैं। इस दृष्टि से विद्यालय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ कराई जा सकती है:

☆ महीने में किसी शनिवार को इससे संबंधित रोलप्ले, क्विज, व्याख्यान आदि आयोजित किए जा सकते है।

क्विज के प्रश्नों के लिए इस QR कोड को स्कैन कर प्रश्न प्राप्त किया जा सकता है।



☆ सड़क सुरक्षा के स्वर्णिम नियमों को दीवार पर लिखवाया जा सकता है या फ्लेक्स लगाया जा सकता है।



☆ सरकार के विभिन्न विभाग किस तरह सड़क सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं इनका दीवार लेखन या फ्लैक्स लगाया जा सकता है। (JCERT– कक्षा:7 की पाठ्यपुस्तक 'सामाजिक एवं राजनितिक व्यवस्था' का पाठ सं. 8 में चार्ट दिया गया है)

☆ 'गुड सेमिरटन' के विषय में जानकारी देकर मॉक ड्रिल करवाया जा सकता है।

☆ 'सड़क सुरक्षा दल' के रूप में कुछ विद्यार्थियों को चिह्नित किया जा सकता है, जो जागरूकता सम्बन्धी कार्यों का नेतृत्व करेंगे।

☆ रैली, स्लोगन, जागरूकता गीत, रोल प्ले, रन फॉर सेफ्टी, पेंटिंग, निबंध, कविता जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जा सकता है।

☆ ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के विषय में विद्यार्थियों को उन्मुख किया जा सकता है।

☆ विशेष अवसर पर शपथ दिलाई जा सकती है।

सड़क सुरक्षा शपथ

Road Safety Pledge **शपथ पढ़िए** / Read Pledge

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा–

दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे।

कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे।

कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे।

वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे न दखेंगे।

हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन करायेंगे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

जय हिन्द, जय भारत।

सुनियोजित संगठन

विद्यालय नेतृत्व में ये सारे कार्य सुनियोजित ढंग से हो सकें इसके लिए एक सुनियोजित संगठन की आवश्यकता होगीस इसमें विद्यालय नेतृत्वकर्ता क्षमताओं का आकलन करते हुए विद्यार्थी, शिक्षक, समिति सदस्यों, समुदाय की भागीदारी के साथ एक संगठन बना सकते हैं।

क्रियान्वयन

इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सत्र के प्रारंभ में ही एक कैलेंडर बनाई जानी चाहिएस महीने में कम–से–कम एक बार इससे संबंधित कोई गतिविधि होनी चाहिए।

हमें यह उम्मीद है कि यह सामग्री विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में सड़क–सुरक्षा के संबध में विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण एवं जागरूकता लाने में उपयोगी होगीस आपने भी अपने विद्यालय में इससे संबंधित कुछ प्रयास किए होंगे एवं इस सामग्री से लाभ उठाते हुए आप आनेवाले दिनों में भी कुछ क्रियाकलाप करेंगे आपके प्रयास हम तक पहुँच पाएँ इसके लिए अपनी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) हमें दिए गए लिंक के माध्यम से दे सकते हैं https://forms-gle/fTtpqsMuBN9wRgqv7

सन्दर्भ :

1- https://morth-nic-in/hi/about&road&safety

2- https://www-prabhatkhabar-com/state/jharkhand/ranchi/oad&accident&in&jharkhand&lives&of&people&taking&high&speed&of&the&vehicle&srn

3- https://www-bhaskar-com/local/jharkhand/ranchi/news/3513&killed&in&road&accident&in&jharkhand&average&10&people&are&dying&every&day&130250806-html

4- https://hindi-news18-com/news/jharkhand/ranchi&rishabh&of&ranchi&is&campaigning&for&road&safety&5266031-html

5. राज्य संदर्भित सामग्री झारखंड – विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम

अतिरिक्त पठन सामग्री

6. https://morth-nic-in/sites/default/files/road_safety_books-pdf
(सड़क सुरक्षा से संबंधित विशेष जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं)

7. https://diksha-gov-in/play/collection/do_31281056297461350415751\contentId:do_313039854246453248111195 (अध्याय–8, पाठ्यपुस्तक कक्षा–7, JCERT)

8. https://diksha-gov-in/play/collection/do_31281056297461350415751\contentId¾do_312875585277812736116041 (वर्कशीट)

छीजन की चुनौती और विद्यालय नेतृत्व की भूमिका



अमाद उद्दीन रागिब
क्रमित उच्च विद्यालय अमलाबाद चन्दनकियारी (बोकारो)

हर साल झारखंड में कुछ बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं। यह उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के साथ–साथ देश और राज्य की साक्षरता दर को भी कम करता है जिससे सामाजिक विकास प्रभावित होता है। झारखंड में स्कूली शिक्षा में छीजन एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है जिसपर विद्यालय नेतृत्व को व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

आप विद्यालय की शिक्षा और उनसे जुड़े किसी भी सर्वेक्षण के आंकड़ों को देख लें, आपको हर सर्वेक्षण और रिपोर्ट में कमोबेश एक जैसी स्थिति देखने को मिलेगी और वह स्थिति यह होगी कि कुछ प्रतिशत बच्चे अपनी शिक्षा को पूर्ण किये बिना विद्यालय छोड़ रहे हैं।

छीजन एक ''हमेशा नामांकित बच्चा'' है जो शिक्षा के अंतिम स्तर को पूरा नहीं करता है जिसके लिए उसने दाखिला लिया है और वर्तमान में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जा रहा है। सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम और शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित कर रही है लेकिन छीजन की समस्या को समाप्त किए बिना सभी बच्चों तक शिक्षा के लक्ष्य को पहुँचाना असंभव है।

छीजन दर को शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा अपव्यय माना जाता है।

कई छात्र बुनियादी कौशल, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं। उनका समय से पहले विद्यालय से संबंध विच्छेद शैक्षिक संसाधनों की बर्बादी का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही, इससे जुड़े लोगों की कार्य क्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। विद्यालय नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह उन सभी कारकों पर अपनी नजर रखें जो छीजन को बढ़ा सकते हैं या छीजन की परिस्थिति को उत्पन कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इसके सभी पक्षों से अवगत होना जरूरी है। अतः इस विषय पर विद्यालय नेतृत्व के साथ एक विस्तृत चर्चा और इसके के सभी पक्षों पर एक विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।

आइए, बच्चों के स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारणों पर चर्चा करते हैं।

छीजन का मतलब यह समझा जाता कि बच्चे विद्यालय छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन, इसको अगर एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब यह भी होता है कि बच्चे विद्यालय आते हैं पर उन्हें हम विद्यालय से लंबी अवधि तक जोड़े रख पाने में विफल रहते हैं। छीजन लेंगीक असमान्ता से भी प्रभावित है और एक ही समाज और एक ही परिवार में लड़कियों और लड़कों के छीजन के कारण भिन्न भिन्न हो सकते है। बच्चों के छीजन को हम निम्नलिखित स्वरुपों में देख सकते हैं।

★ पारिवारिक कारण

★ घरेलू काम–काज में मदद एवं आर्थिक स्थिति को छीजन के पारिवारिक कारणों में एक बड़े कारण के रूप मे देखा गया हैं। लड़कियों के सम्बन्ध में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में कुछ परिवार केवल इसलिए पढ़ाई से लड़कियों को अलग कर देते हैं क्योंकि वह उनके अनुसार 'बड़ी' हो गई हैं और उन्हें अब घर के काम को सीखना चाहिए। इसमें भी कई तरह की स्थिति होती है। कुछ परिवार चौथी पाँचवी कक्षा तक यह निर्णय लेते हैं, कुछ वर्ग 8 तक और माध्यमिक स्तर पर तो ऐसे निर्णय लेने वालों की संख्या अच्छी–खासी है। माध्यमिक स्तर पर परिवार का यह निर्णय उनके विवाह से भी जुड़ जाता है। ऐसी मान्यता बनी हुई है कि यदि लड़की ज्यादा पढ़ लेगी तो उसके योग्य वर नहीं मिल सकेगा। ऐसी विचारधारा तो हाल के वर्षों तक कुलीन कहे जाने वाले वर्ग में भी देखी जाती थी। हालांकि यह मान्यता पूर्व की अपेक्षा कुछ कम हुई है लेकिन अभी भी इसे देखा जा सकता है। इसी तरह अगर उसी परिवार में लड़कों की बात करें तो यह निर्णय आर्थिक कारणों से प्रभावित होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहने के कारण लड़कों की आयु बढ़ते ही उन्हें रोजगार में लगाने या रोजगार योग्य बनाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। बाल श्रम कानूनों की मजबूती ने कुछ अंकुश लगाया है पर शहरी क्षेत्रों में यह अभी भी लघु उद्योगों में देखा जा सकता है।

गतिविधि 1

सीमा कक्षा 6 में पढ़ रही है उसका भाई कक्षा 7 में पढ़ता है। सीमा की माँ चाहती है कि वह घर के काम को सीखे क्योंकि उसे आगे यही करना है। उसके पिता इस से सहमत हैं और वह सीमा के भाई को भी अपने साथ अपने काम पर ले जाना चाहते हैं। सीमा और उसके भाई के पास अपना कोई विचार नहीं है।

☆ सीमा के माता–पिता ऐसा क्यों सोचते हैं?

☆ सीमा और उसके भाई के पास अपना विचार क्यों नहीं है?

☆ विद्यालय नेतृत्व को क्या करना चाहिए?

★ माता–पिता के अतिरिक्त किसी और पर आश्रित बच्चों की शिक्षा बहुत चुनौती पूर्ण होती है। कई बार पारिवारिक कलह या फिर किसी दुर्घटना के कारण बच्चों के सर से माँ–बाप का साया उठ जाता है या उनके रहते भर में भी उन्हें किसी दूसरे के भरोसे जीवन गुजारना पड़ता है। यह बच्चे कब ड्राप–आउट हो जाएँ कोई नहीं कह सकता है।

★ कई बच्चे मानते हैं कि अगर उन्हें अपने माता–पिता के समान काम करना है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वे प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ देते हैं। भारतीय सांख्यिकी विभाग के एक सर्वेक्षण में शामिल 30% से अधिक बच्चों ने पढ़ाई में रुचि की कमी दिखाई, उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना पसंद किया क्योंकि एक तरफ स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था, वह मुश्किल से ही उन्हें आकर्षित कर रहा था और वह यह मान रहे थे कि उन्हें अपने परिवार के ही आर्थिक गतिविधि को करना है इसलिए पढ़ाई उनके लिए गैर जरूरी है।

★ सामाजिक कारण

★ समाज में अभी भी कुछ लोगों के बीच लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग और लड़कों की शिक्षा के लिए अलग दृष्टिकोण है। इसका एक मुख्य कारण रोजगार की जरूरत भी है। समाज में मान्यता बनी हुई है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। अब चूँकि घर गृहस्ती में आर्थिक जवाबदेही लड़को पर आनी है इसलिय उसकी शिक्षा ज्यादा जरूरी मान ली जाती है। लड़कियों का 'काम' 'घर का काम' करना है इसलिए लड़की की पढ़ाई महत्त्वहीन हो जाती है। इस सोच की वजह से दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के बीच ड्रापआउट कोई समस्या नहीं है बल्कि एक उत्तम समाधान है।

★ असुरक्षा की भावना के कारण लड़कियों के लिए पढ़ाई जारी रखना विशेष रूप से कठिन हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों को जिन परिस्थितियों का सामना करना होता है उनमें उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी है। कुछ जगहों पर उनके विद्यालय आने जाने के मार्ग में उन्हें मनचलों का समाना करना पड़ता है। लोक लाज के कारण वह ऐसे विषयों पर चुप हो जाती हैं या विद्यालय छोड़ देने का निर्णय लेने को विवश हो जाती हैं।

गतिविधि 2

रजिया कक्षा 9 की छात्रा है। उसे कुछ लड़के विद्यालय आने–जाने में परेशान करते हैं। वह इस से बहुत परेशान रहती है। किसी और को बताने में डरती है कि इससे उसकी बदनामी होगी। वह स्कूल जाना छोड़ देती है।

☆ रजिया अपनी समस्या किसी को बताना क्यों नहीं चाहती?

☆ विद्यालय प्रधानाध्यापक को ऐसी समस्याओं को पता करने और इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए?

★ स्कूली कारण–

बच्चों के विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों में स्कूली कारक भी है। यह कारक अति महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इनके तीव्र सुधार की भरपूर गुंजाईश है और यह विद्यालय के नियंत्रण में है।

★ स्कूल की खराब सुविधाओं के कारण लड़कियों को स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन शौचालय की आवश्यकता के साथ मासिक धर्म के समय उन्हें एक अच्छे शौचालय (भस्मीकरण यंत्र से युक्त) की जरूरत होती है। विद्यालय में क्रियाशील शौचालय की कमी लड़कियों को विद्यालय से अलग होने पर मजबूर करती है।

2. विद्यालयी शिक्षा में पिछड़ने के कारण भी बड़ी संख्या में बच्चे छीजन का शिकार होते हैं। जब एक बच्चे को विद्यालय में नामांकन के बाद उसे कक्षा स्तर के अनुरूप शिक्षा नहीं मिल पाती है तो वह लगातार पिछड़ता जाता है। कुछ दिन या एक–दो वर्ष तो वह विद्यालय आता है लेकिन साल दर साल बदलती कक्षा में अपने आप को पिछड़ता देख एक दिन वह हमेशा के लिए अपने विद्यालय और अपनी शिक्षा को अलविदा कह देता है।

3. विद्यालय का माहौल भी कई बार ड्रापआउट का कारण बन जाता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय ज्यादा सख्ती दिखाते हैं हालांकि उनका यह व्यवहार बच्चों को सिखाने के लिए हो रहा होता है। फिर भी इससे जो भय का वातावरण बच्चों के मन में बनता है उससे वह विद्यालय जाने से कतराता है। इस स्थिति में कुछ अभिभावक

वास्तविक स्थिति को जाने बिना यह मान लेते हैं कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अतः उसे स्कूल से अलग कर दूसरे काम में लगा देते हैं।

4. विद्यालय में जब बच्चे ज्ञान अर्जन कर रहे होते हैं तब उनके अन्दर अपनी पहचान और मान सम्मान की भावना भी जागृत हो रही होती है और इसे लेकर उनके मन में एक अलग प्रकार की संवेदना होती है। इसकी कई बार अनजाने में अनदेखी हो जाती है और यह अनदेखी उनको इस तरह से विचलित कर देती है कि वे विद्यालय और उससे जुड़े लोगों से अलगाव महसूस करने लगते है इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है और उनके ड्रापआउट होने की संभवना बनने लगती है।



5. दिव्यांग बच्चे स्वयं को आम बच्चों से अलग समझते हैं लेकिन उनके मन मे विद्यालय के प्रति एक आकर्षण होता है क्योंकि यह पहली जगह होती है जहाँ उन्हें उनके साथ कुछ बेहतर होने की आशा होती है। कुछ मामलों में उन्हें अलग व्यवस्था की जरूरत भी होती है। लेकिन जब उनके साथ विद्यालय में उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था एवं सहयोग नहीं मिलता है तो उनका मन विद्यालय से टूट जाता है। कई बार तो उन्हें अपनी दिव्यांगता के कारण उपेक्षा का भी अहसास होता है। ये कारण दिव्यांग बच्चों के छीजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

6. झारखण्ड राज्य सामाजिक असमानता की समस्याओं से भी जूझ रहा है। समाज में कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से शारीरिक, स्वास्थ्य या फिर सामाजिक स्थिति में भिन्न होने पर उनके द्व ारा अपने साथियों से भेदभाव या शत्रुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो उनकी स्थिति असहज हो जाती है। इससे बचने के लिए उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है।

गतिविधि 3

अर्नव कक्षा 3 में पढ़ता है। उसकी एक आँख छोटी और एक बड़ी है। उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है पर वह देखने के लिए अपनी गर्दन को हल्का टेढ़ा रख कर देखता है। उसके कक्षा के साथी उसे "काना" कह कर चिढ़ाते हैं। उसे यह अच्छा नहीं लगता और वह स्कूल जाना नहीं चाहता है।

★ अर्नव के साथियों का ऐसा करना उन्हें खुद क्यों खराब नहीं लगता है?

★ शिक्षक ऐसी गतिविधियों पर नजर रखें इस हेतु विद्यालय प्रधान को क्या करना चाहिए?

उपरोक्त कारणों और गतिविधियों पर चर्चा के उपरान्त विद्यालय नेतृत्व से निम्न हस्तक्षेप की अपेक्षा की जाती है।

» विद्यालय नेतृत्व को यह समझना होगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास का अर्थ केवल उन बच्चों का विकास नहीं है जो नियमित विद्यालय आ रहे है। विकास का अर्थ पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के विकास से होना चाहिए। विद्यालय नेतृत्व को विद्यालय और समाज के भीतर स्वयं को इस प्रकार स्थापित करने की आवश्यकता है। उसे विद्यालय से जुड़े सभी पक्षों विशेषकर छीजन के कारणों के उन्मूलन में सामाजिक सहयोग प्राप्त हो सके।

» विद्यालय नेतृत्व को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति का नियमित अन्तराल पर अनुश्रवण हो रहा है। इस अनुश्रवण में अनियमित बच्चों और उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत बातचीत करनी चाहिए। इन अनियमित बच्चों में कोई बच्चा ऐसा भी मिल सकता है जो किसी ऐसी समस्या से संघर्ष कर रहा हो जो आगे चलकर उसके छीजन का कारण हो सकता है। नियमित अनुश्रवण और बातचीत से विद्यालय नेतृत्व बच्चे और अभिभावक को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर उसके आत्मविश्वास को सबल कर सकता है और भविष्य में होने वाले छीजन को इसके माध्यम से रोक सकता है।





» सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक कारणों से होने वाले छीजन पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि यह सारे कारक सामाजिक मान्यताओं से जुड़े हैं इसलिए इन पर अंकुश लगाने के लिए समाज में फैली कुरीतियों और त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं को समाप्त करने के प्रयास में जन–जागरूकता एक बेहतर विकल्प है। हर क्षेत्र में छीजन के लिए अलग–अलग सामाजिक कारण हो सकते है। विद्यालय नेतृत्व को अपने क्षेत्र की छीजन से जुड़ी समस्याओं को चिह्नित करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं पर विद्यालय प्रबंध समिति के साथ मिलकर जन–जागरूकता कार्यक्रम इस तरह आयोजित किया जाना चाहिए की लोगों में एक संवेदना जागृत हो और समाज अपनी कुरीतियों और त्रुटिपूर्ण विचारधाराओं में सुधार के लिए तैयार हो सके।



» विद्यालय में सुविधाओं के अभाव के कारण लड़कियों को स्वच्छता संबंधी जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छे शौचालय के बिना स्वच्छता के दृष्टिकोण से विद्यालय के संरचनात्मक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अच्छे शौचालय से तात्पर्य एक ऐसे शौचालय से है जिसमें निर्बाध जल की व्यवस्था हो। लड़कियों के लिए शौचालय के साथ भस्मीकरण यंत्र लगा हो। ऐसी व्यवस्था से लड़कियों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में कोई समस्या नहीं आती है।



★ विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है। विद्यालय नेतृत्व से अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय के शिक्षकों के मध्य ऐसी प्रक्रिया स्थापित करें जिससे विद्यालय के शिक्षक बच्चों को गुणवत्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें और जवाबदेह बन सकें। बच्चों का नियमित रचनात्मक आकलन होना चाहिए ताकि वैसे बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके जो अधिगम के लिए संघर्ष कर रहें हैं। ऐसे बच्चों के लिए शैक्षणिक तकनीक व प्रक्रिया में बदलाव लाकर या फिर रिमेडियल की व्यवस्था कर सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। समय पर मिले सहयोग से इस कारण होने वाले छीजन को रोका जा सकता है। रीमेडीयल या अतिरिक्त कक्षा का निर्णय विद्यालय नेतृत्व के द्वारा ही लिया जाना उचित है क्योंकि ऐसे बच्चों को कई शिक्षक की जरूरत हो सकती है।

★ विद्यालय में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को सुनिश्चित कराने में विद्यालय नेतृत्व के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए। छीजन के वह कारक जिसमें बच्चे की भावना आहत होने से वह विद्यालय से दूर हो जाता है उसे संबंधों को सुधार कर ही ठीक किया जा सकता है। बच्चों को प्यार मिलने से वह शिक्षक को सहयोग देने लगते हैं जिससे उनका अधिगम स्तर बढ़ने लगता है।

★ दिव्यांग बच्चों को इस तरह की विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे उनको सामान्य बच्चों जैसा अनुभव हो। उनको स्नेह का वातावरण उपलब्ध करा कर सामान्य बच्चों के साथ आसानी से पढ़ाया जा सकता है। जब उनके साथ बराबरी का व्यवहार होने

लगता है तो जिस आशा से ऐसे बच्चे विद्यालय आते हैं वह पूरी होने लगती। इन सभी बच्चों के छीजन को विद्यालय नेतृत्वकर्ता एक बेहतर रणनीति बना कर रोक सकता है।



» राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दो पहलों का उल्लेख किया गया है जो छीजन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए की जाएंगी। पहली है – सभी छात्रों को कुशल और पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना। दूसरी है – प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा केंद्र स्थापित करना। पहली पहल में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका सीधे सीधे महत्वपूर्ण होगी। दूसरी पहल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र का विचार दिया गया है। विद्यालय नेतृत्व प्रवाशी मजदुरों के बच्चों के लिए भी यदि किसी नवाचारी विधि से शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं तो यह लाभकारी हो सकता है। इस तरह का प्रयास अन्य विद्यालयों के लिए अनुकरणीय हो सकता है।

» विद्यालय नेतृत्व को छात्रों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और उनमें रुचि जगाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का अभ्यास कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम का मिश्रित उपयोग कर बच्चों को में डिजिटल माध्यम के उपयोग से शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, ऐसी स्वतंत्रता बच्चों को नयी तकनीक के साथ सीखने का आकर्षण उपलब्ध कराएगी। क्योंकि कुछ छात्र स्मार्टफोन एप्लिकेशन और नए माध्यम के प्रति एक विशेष आकर्षण रखते हैं और कई बार उन्हें इस कारण से परम्परागत शिक्षा से विमुख होते देखा गया है।

बच्चों की उपस्थिति में सुधार के प्रयास

चुनौती :

उत्क्रमित उच्च विद्यालय अमलाबाद चंदनकियारी बोकारो कोलियरी क्षेत्र में अवस्थित है। विद्यालय की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विद्यालय गाँव के उत्तर दिशा में अंतिम छोर पर दामोदर नदी के किनारे पर है। देखने में विद्यालय के आस–पास के दृश्य बहुत ही मनोरम हैं किन्तु गाँव के अंतिम छोर में होने के कारण बच्चों को विद्यालय आने के लिए बहुत चलना पड़ता है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति सामान्य रहती है किन्तु शतप्रतिशत उपस्थिति के लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्या आ रही थी

इन सब प्रयास के माध्यम से विद्यालय नेतृत्व के द्वारा छीजन की समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है।

–: प्रयास ही सफलता की कुंजी है :–

दहेज प्रथा व उसके उन्मूलन में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका।



अंजनी आनंद
TGT (SOCIAL SCIENCE) GOVT- MS GANESHPUR, BALUMATH, LATEHAR

परिचय

झारखंड में दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है जो कानूनी रूप से अवैध होते हुए भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। झारखंड जैसे विकासशील एवं अति पिछड़ा राज्य जहाँ गरीबी, पलायन, रोजगार की कमी एवं अशिक्षा जैसी मूलभूत समस्याएँ राज्य के विकास को अवरुद्ध कर रही है वहीं कुछ प्रचलित सामाजिक कुरीतियों जैसे डायन प्रथा एवं दहेज प्रथा भी यहाँ की परपंरा एवं सांस्कृतिक विरासत पर भी एक कलंक के समान मौजूद है। दहेज प्रथा पूरी तरह से इस सोच पर आधारित है कि समाज में श्रेष्ठ पुरुष हैं, और महिलाओं का समाज में महत्व नही है। इस तरह की सोच, विचारधारा एवं समझ, परिवार व समाज एवं राज्य के लिए निदंनीय है। बदलते वक्त के साथ दहेज प्रथा लालच की पराकाष्ठा का स्वरूप बनता जा रहा है एवं जिसकी पूर्ति नहीं होने पर महिलाओं के वैवाहिक जीवन, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। महात्मा गांधी ने दहेज प्रथा के बारे में लिखा था कि ''जो भी व्यक्ति विवाह शादी में दहेज को जरूरी शर्त बना देता है वह अपने शिक्षा, अपने राज्य एवं अपने देश को बदनाम करता है। साथ ही साथ पूरी नारी जाति को अपमानित करता है।'' बुद्धिजीवी, विचारक, आम एवं खास हर तरह के इंसान दहेज जैसे अपराध को रोकने हेतु चर्चा करते है लेकिन वास्तविक जीवन में इस जघन्य अपराध को अपने आस–पास, यहाँ तक की खुद अपने परिवार में देखकर भी अनदेखा करते हैं जो कि शर्म की बात है।

झारखंड में इस कुप्रथा को खत्म करने में विद्यालय प्रमुखों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है । हम विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को इस कुप्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें जागरूक करेंगे ताकि वो इसके समूचित उन्मूलन में खुद भागीदार बन सकें एवं समाज के हितधारकों को भी संवेदनशील बना सकें ।



दहेज क्या है ?

21वीं सदी में विकासशील भारत में दहेज एक अभिशाप बन गया हैं। दहेज का जाल हर तरफ फैला है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु भारत में कई कानून बने है परंतु उन कानूनों का हमारे रूढ़ीवादी सोच वाले लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह दहेज लेना गर्व की बात समझतें हैं लेकिन यह एक शर्म की बात है। दहेज प्रथा का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। दहेज शब्द अरबी भाषा का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसका अर्थ होता है–भेंट या सौगात । विवाह के समय कन्यादान में वधू के माता–पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति में से कन्या को कुछ धन, वस्त्र ,आभूषण, आदि देना ही दहेज है। विवाह के समय लड़के वालों द्वारा लड़की के परिवार से नगद या किसी प्रकार की कीमती वस्तु को उपहार बताकर माँगने को दहेज लेना कहते हैं।

दहेज से सबंधित तीन स्थितियां हैः

1. विवाह के पूर्व 2. विवाह के समय 3. विवाह के उपरांत

झारखंड में दहेज प्रथा के क्या–क्या कारण है ?

पुराने रीति रिवाजः–

लोग दहेज लेने के लिए पुराने रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं और कहते है कि यह सदियों से चली आ रही है।

पुरूष प्रधान समाजः–

झारखंड में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने को अधिकार नहीं होता है जिसके कारण दहेज के लिए महिलाओं का शोषण होता है, उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है ताकि वह दहेज लाए। प्रारंभ से ही बच्चियों को यह बताया जाता है कि उन्हें पुरुषों की बात माननी चाहिए इसी में उनकी भलाई है। जिसके कारण वह अपने आप को कमजोर मानने लगती है।

अशिक्षा व सामाजिक प्रतिष्ठाः–

हमारे देश में आज भी कई लोग पढ़े लिखें नही है जिसके कारण वे सोचते हैं कि दहेज नही देगें तो उसके बेटी की शादी नही होगी। साथ ही साथ आज के समय में शिक्षित लोग भी प्रतिस्पर्धा एवं सम्मान से इस दहेज को जोड़कर देखते है एवं दहेज की माँग करते है।

सांवला रंग या अन्य कोई शारीरिक विकारः आज के समय में हरेक परिवार अपने घर में सुंदर एवं गोरी लड़की को ही पुत्रवधु के रूप में देखना चाहता है जिसका प्रमाण अखबार के इस्तेहारों एवं इंटरनेट में साझा की गयी जानकारी से प्राप्त होता है। अतः जिनकी बच्चियाँ सांवली होती है वो दहेज में ज्यादा पैसे देते है।

बेरोजगारीः–

बेरोजगार युवको के पास शादी का प्रस्ताव जाने के बाद वे दहेज की मांग यह कहते हुए करते हैं कि वे इस पैसे का इस्तेमाल कुछ व्यवसाय करने मे करेंगे एवं आपकी बेटी को खुश रखेंगे।

व्यवहारिक रूप से बेटियों का पैतृक संपत्ति में हिस्सा नही होना–

झारखंड में कानूनी रूप से अपने पिता के संपत्ति में बेटियों का अधिकार तो है, परन्तु व्यवहारिक रूप से पिता के संपत्ति में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। बेटियां भी सामाजिक मानसिकता के कारण पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लेना उचित नहीं समझती है। इस कारण लड़के पक्ष के लोगों को लगता है कि लड़की पक्ष से दहेज में जो मिल गया वो ले लें फिर बाद में तो कुछ मिलना नहीं है। लड़की के पिता की मानसिकता रहती है कि अपने बेटी को दहेज देकर उससे अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेतें हैं। इन सबके बीच झारखण्ड में आदिवासी समाज में बेटियों सम्पति का उत्तराधिकार तो नहीं है लेकिन इस समाज में दहेज प्रथा के बदले वधू मूल्य की प्रथा विद्यमान है ।

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम

महिलाओं लड़कियों का शोषण व घरेलु हिंसा में बढ़ोतरीः– दहेज के लिए महिलाओं का शोषण होता है, उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाता है ताकि वे अपने घर से और पैसे लाए। प्रताड़ना इस हद तक बढ़ जाता है कि लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती है। सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कि 2016 की रिपोर्ट की अनुसार 7621 महिलाएँ या लड़कियों को दहेज के लिए मार दी गई।

लड़कियों के साथ भेदभावः–

दहेज प्रथा के कारण जन्म से ही लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है । लड़कियों को लेकर समाज की आम धारणा है कि लड़कियां पराई धन होती है, वे दूसरों के घर जाएगी । अतः उनकी पढ़ाई, खानपान पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ।

घटता लिंगानुपातः–

दहेज प्रथा के कारण लोग लड़कियों को पसंद नहीं करतें हैं जिसके कारण जन्म से पहले ही उन्हें कोख में ही मार दिया जाता है जिसके कारण झारखंड में आज लिंगानुपात (1000 पुरुषों की तुलना में 947 स्त्रियां) में अंतर देखा जा सकता है ।

कई महिलाएँ अविवाहित रह जाती हैंः–

देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती हैं क्योंकि उनके माता–पिता विवाह पूर्व दहेज की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं ।

महिलाओं का वस्तुकरणः

समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के अवसरों हेतु एक निवेश की तरह है। यह महिलाओं को केवल वाणिज्य के लेख (articles of commerce) के रूप में प्रस्तुत करता है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधः

कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है, इसमें भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मौत तक शामिल है ।

सच तो यह है कि हमारे देश मे दहेज प्रथा से भी भ्रष्टाचार, रिश्वत, मिलावट, जमाखोरी, काला–बाजारी, तस्करी (स्मगलिंग) आदि सभी पापों को बढ़ावा मिला है। दहेज जुटाने के लिए आदमी सब प्रकार के पाप और कानूनी अपराध तक करने को तैयार हो जाता है । सज्जन, ईमानदार आदमी को भी यह प्रथा दुर्जन एवं बेईमान बनने पर मजबूर कर देता है।

दहेज उन्मूलन के लिए किये गए सरकारी प्रयास

सरकार, अपने स्तर से दहेज के अभिशाप को मिटाने के लिए कृ तसंकल्प है। दरअसल, दहेज एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो सदियों से चली आ रही है। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए दहेज–विरोधी कानून बना रखा है, फिर भी पूरे देश मे प्रत्येक साल काफी बड़े पैमाने पर नवविवाहित महिलायों को इसकी वजह से अपने प्राण त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह कुप्रथा केवल अनपढ़ों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अच्छे सुशिक्षित परिवारों में भी इसने काफी गहरी जड़ जमा रखी है ।

सच्चाई यह है कि समाज–सुधार का कोई भी कार्य केवल कानून के सहारे नहीं किया जा सकता । जनमत जगाकर लोगों में दहेज–विरोधी वातावरण बनाना जरूरी है । हमारे ध र्माचार्य और संत–महात्मा इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकतें हैं ।

दहेज उन्मूलन निषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानः–

इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या इसमें सहयोग करने में दोषी पाए जाने पर 05 वर्ष की कैद या 15000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है । दहेज के लिए उत्पीड़ित करने में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड सहिता की धारा 498–। जो पति या उसके रिश्तेदार द्वारा कीमती सामान या वस्तुओं के अवैधानिक मांग से जुड़ा है में 03 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि लड़की के विवाह के सात साल के भीतर असमान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि दहेज उत्पीड़न के कारण उसकी मौत हुई है तो उसे भारतीय दंड सहिता की धारा 304–ठ के अन्तर्गत कम से कम 07 साल की सजा का प्रावधान है।

अधिनियम से जुड़ी चयनित प्रमुख धाराएँः–

धारा 2: दहेज का मतलब है किसी प्रकार के सम्पति का लेन–देन प्रत्यक्ष या परोक्ष से करना एवं एक पक्षकार द्वारा दूसरे को इसके लिए बाध्य करना ।

धारा 3: दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 05 वर्ष के कारावास के साथ–साथ पन्द्रह हजार रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है।

धारा 4: यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते है तो उन्हें कम से कम छः मास से लेकर 02 वर्ष तक की सजा या दस हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है।

धारा 4: – किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र या पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पति का कोई प्रस्ताव दहेज की श्रेणी में आता है। ऐसे में कम से कम छः माह से 05 वर्ष की अधिकतम सजा या पंद्रह हजार रूपये जुर्माना हो सकता है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दहेज उन्मूलन के क्षेत्र में झारखंड सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर–बसर करने वाले परिवारों की बच्चियों को शादी के समय सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत झारखंड राज्य अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की कन्या को विवाह के अवसर पर 30 हजार रुपए आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाता में प्रदान की जाती है। इसके अलावे झारखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई। सवित्रिवाई फुले किशोरी समृद्धि योजना भी बालिका शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। इन प्रयासों को झारखण्ड सरकार द्वारा इस दिशा में एक सार्थक प्रयास माना जायेगा।

झारखंड में विद्यालय नेतृत्व का दहेज प्रथा उन्मूलन में भूमिकाः–

दहेज उन्मूलन पर चाहे जितनी भी बातें हो जाये, चाहे जितने भी कानून बन जाये लेकिन जबतक लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। लोगों की मानसिकता बदलने में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इतिहास गवाह है कि सामाजिक परिवर्तन आने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब तक लोगो में शिक्षा व जागरूकता नहीं आता तब तक इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है। इस कार्य के लिए हमारा विद्यालय एक सशक्त माध्यम हो सकता है। वर्तमान समय में हमारे झारखण्ड में विद्यालय की पहुँच जन–जन तक हो चुकी है। विद्यालय नेतृत्व द्वारा निम्न योजना बनाकर दहेज प्रथा उन्मूलन का सार्थक प्रयास किया जा रहा है ।

विद्यालयी कार्यक्रम में दहेज प्रथा पर कार्यशाला आयोजित कर – विद्यालय नेतृत्व की पहुँच जन–जन तक होती है । विद्यालय अपने कार्यक्रमों खासकर प्रबंधन समिति की बैठकों में, विद्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दहेज उन्मूलन पर चर्चा या कार्यशाला आयोजित कर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है।

जागरूकता रैलियों द्वारा–

झारखण्ड में हमारे विद्यालय समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर अपने पोषक क्षेत्र में रैलियां निकाला करता है । इन रैलियों में दहेज प्रथा उन्मूलन के नारों को शामिल कर लोगों का ध्यान दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बालिका शिक्षा की दिशा में लाने का प्रयास किया जाता है ।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर–

झारखण्ड में दहेज उन्मूलन के लिए एक अनुकूल परिस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तथा आदिवासी समाज मे दहेज प्रथा नहीं के बराबर है। झारखण्ड में स्थानीय जनप्रतिनिधियों में आदिवासी जनप्रतिनिधियों की बहुतायत है विद्यालय नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठक कर उन्हें दहेज प्रथा के कुप्रभाओं से अवगत करायेंगे एवं उनके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जायेगा। आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों इन कार्यों में संबल प्रदान करेंगे।

बाल संसद के माध्यम से–

झारखण्ड के विद्यालयों में बाल संसद काफी सशक्त है। बाल संसद को उनके कार्यों के साथ–साथ उन्हें सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिया प्रेरित किया जाता है। बाल संसद योजना बनाकर 15 दिनों में एक बार विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जाकर रैलियों, नारों, एवं नुक्कड़ नाटकों द्वारा दहेज प्रथा एवम बाल विवाह जैसे कुरीतियों पर जागरूकता फैलाने का कार्य करतें हैं।

मीना मंच/किशोरी मंच के द्वारा–

विद्यालय के ऊँची कक्षाओं में पढने वाली छात्राओं को मीना–मंच/किशोरी मंच से जोडकर उनके माध्यम से दहेज के कुप्रभाओं से समाज को जागरूक करना काफी श्रेयस्कर रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब समाज में बेटियां इस प्रथा पर खुलकर बोलना शुरू करेगी तो समाज को संवेदनशील बनना होगा, देर–सबेर इस कुप्रथा का खात्मा अवश्य ही होगा।

छात्रों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कर–

विद्यालय छात्रों के बीच दहेज प्रथा उन्मूलन पर वाद–विवाद,प्रश्नोत्तरी,निबंध,भाषण इत्यादि प्रतियोगता का आयोजन कर छात्रों को दहेज के कुप्रभाओं से अवगत कराते हैं। जब हम अपने छात्र–छत्राओं को दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए मानसिक तौर पर सशक्त बना देंगें। तभी हम पूरे तौर पर दहेज उन्मूलन को लेकर समाज के मानसिकता में परिवर्तन की उम्मीद रखें। चूँकि जब प्रत्येक परिवार में दहेज विरोधी व्यक्ति खड़ा होगा, तभी जाकर बड़े पैमाने पर समाज से दहेज रूपी दानव को खत्म किया जा सकता है।

विद्यालय के शिक्षकों द्वारा आदर्श प्रस्तुत कर–

शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता का दर्जा प्राप्त है। समाज में शिक्षक काफी संवेदनशील एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। विद्यालय जब दहेज प्रथा उन्मूलन पर जागरूकता फैलाने का काम करेगा तब सबसे पहले उसे अपने शिक्षकों से आदर्श प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना होगा। चूँकि वैसे व्यक्ति का समाज में प्रभाव ज्यादा होता है जिसके कथनी और करनी एक जैसी हो।

स्वयं सहायता समूह एवं माता समितियों को सशक्त बनाकर– झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों

में स्वयं सहायता समूह महिलायों का एक समूह है जो काफी सशक्त है। इससे जुडी हुई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी है। झारखण्ड के विद्यालयों में माध्याह्न भोजन योजना सरस्वती वाहिनी माता समिति के द्वारा संचालित होता है। इस समिति में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की माताएँ होती है। विद्यालय नेतृत्व उक्त समितियों को दहेज प्रथा के कुप्रभाओं से अवगत कराकर इनके माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा।

शिक्षार्थियों को दहेज प्रथा रोकने सम्बंधी कानूनी प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से बताकर–

★ विद्यालय अपने छात्रों के बीच दहेज प्रथा रोकने सम्बन्धी निम्न कानूनी प्रावधानों को अपने छात्र–छात्राओं के बीच साझा करेंगें दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेना और देना या इसके लेन–देन में सहयोग करने वालो को कम से कम 5 वर्ष की कैद और कम से कम 15000 का जुर्माना या दहेज की रकम बराबर जुर्माना का प्रावधान है।

★ यदि किसी लड़की की विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित होता है कि उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय आचार दंड संहिता की धारा 304–बी के तहत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है ।

★ जब किसी महिला का पति या उसके रिश्तेदार दहेज के लिए किसी महिला को प्रताड़ित व उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते है और यह अपराध प्रमाणित हो जा है तो भारतीय आचार दण्ड संहिता कि धारा 498–ए के तहत तीन वर्ष का कारावास व जुर्माना हो सकता है।

उक्त के अलावे निम्नलिखित बातों का अनुपालन कर हम दहेज प्रथा को रोकने को प्रयास कर सकतें हैं:

★ बालिकाओं को शिक्षित करना।

★ महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर।

★ समाज एवं परिवार में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करें एवं सरकारी कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओं एवं बेटी पढ़ाओं और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और प्रचार प्रसार कर दहेज प्रथा के खिलाफ समाजिक जागरूकता कार्यक्रम को और दृढ़तापूर्वक लागू करना।

★ कन्या भ्रुरूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को दूर कर।

★ घरेलु हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को सख्ती से लागू कर।

★ गांव स्तर पर गठित बाल सरंक्षण समिति के सदस्यों को इसके बारे में सूचित कर नजदीकी पुलिस केन्द्र में जाकर इसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज कराकर।

दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान में विद्यालय नेतृत्व को प्रमुख भूमिका निभानी है। समाज में विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जिसकी पहुँच समाज में प्रत्येक परिवार तक है।

दहेज प्रथा उन्मूलन से संबंधित विद्यार्थियों एवं अभिवभावकों में जागरूकता के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं :–

1. दहेज क्या है ?

(क) दहेज एक स्थान है।
(ख) दहेज एक सामाजिक बुराई है।
(ग) दहेज एक धर्म है।
(घ) उपरोक्त में से कोई नही है।

2. दहेज लेने के क्या-क्या कारण हो सकतें हैं ?

(क) पुराने रीतिरिवाज
(ख) अशिक्षा
(ग) बेरोजगारी
(घ) उपरोक्त सभी

3. दहेज के क्या-क्या कुप्रभाव होते हैं ?

(क) महिलाओं के साथ मानसिक एवं शारीरिक शोषण
(ख) घरेलु हिंसा में बढ़ोतरी
(ग) घटता लिंगनुपात
(घ) उपरोक्त सभी

4. दहेज प्रथा को कैसे रोका जा सकता हैं ?

(क) बालिकाओं को शिक्षित कर
(ख) महिलाओं को सशक्त बनाकर
(ग) कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाकर
(घ) उपरोक्त सभी

5. दहेज प्रथा सबंधी गलत कथन को चुनें ?

(क) विवाह के समय लड़के वालों द्वारा लड़की के परिवार से नगद या कीमती वस्तुओं को माँगना
(ख) विवाह के पहले या बाद में व्यवसाय करने के नाम पर लड़की वालों से पैसे माँगना
(ग) दहेज न देने पर प्रताड़ित करना
(घ) लड़के के परिवार द्वारा लड़की को दहेज देना

6. सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित हैं ?

(क)लड़कियों से
(ख) लड़कों से
(ग) दोनों से
(घ) दोनों में से किसी से नही

7. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना किससे संबंधित हैं ?

(क) पुरूष (ख) महिला
(ग) बेटी / लड़की (घ) लड़का

8. दहेज प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष पारित किया गया ?

(क) 1961 (ख) 1962
(ग) 1963 (घ) 1964

9. झारखण्ड में किस समाज में दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है ?

(क) ब्राह्मण समाज (ख) अनुसूचित जाति में
(ग) आदिवासी समाज में (घ) पिछड़ा वर्ग

निष्कर्ष–

मौजूदा दौर में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके तहत युवती के माता–पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर ही निर्भर करता है। सीधे कहें तो दहेज को सामाजिक मान–प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है। वर–पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है। प्राचीन परंपराओं के नाम पर युवती के परिवार वालों पर दबाव डाल कर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक न जाने कितने नियम–कानून बनाए जा चुके हैं। लेकिन उनमें से कोई भी असरदार साबित नहीं हुआ है। वर्ष 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैरकानूनी घोषित किए गए। लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज भी वर–पक्ष खुलेआम दहेज की मांग करता है। वर्ष 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विधि आयोग के पास भेजते हुए दहेज निरोधक कानून पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है।

लेकिन सामाजिक संगठनों का कहना है कि महज कानून बनाना इस समस्या का समाधान नहीं है। कई मामलों में इस कानून का दुरुपयोग भी होता रहा है। समाज में हर किस्म के लोग हैं। कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसे समाज का समर्थन नहीं मिले। दहेज आधुनिक समाज के माथे पर कलंक बन चुका है। हैरत की बात यह है कि पढ़े–लिखे लोग भी बेहिचक इसकी मांग करते हैं। इस कलंक को मिटाने के

लिए समाज की सोच और नजरिया बदलना जरूरी है । इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को गैर– सरकारी संगठनों के साथ मिल कर दहेज विरोधी साक्षरता के प्रचार–प्रसार पर जोर देना चाहिए। हमारे समझ से इस मामले में कानून और अदालतें ज्यादा कुछ नहीं कर सकतीं। युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा किए बिना यह समस्या लगातार गंभीर होती जाएगी। इसलिए हम सब को अब आगे आना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी क्योंकि अगर हम आज आवाज नही उठायेंगे तो कल हमारी बेटियाँ ही इसकी शिकार हो सकती हैं और हम सिर्फ अफसोस ही करते रह जायेंगे, अतः हम यह प्रण करें दहेज का करेंगे सम्पूर्ण उन्मूलन। इस कार्य में हमारा विद्यालय नेतृत्व काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सीखने के प्रतिफल में विद्यालय नेतृत्व की भूमिकाः–



भूपेश प्रसाद श्रीवास्तव स० शि० रा० बालक मध्य विद्यालय, पहाड़ीटोला, राँची
तारा कुमारी प्र० प्र० अ० रा० मध्य विद्यालय, बुटी, राँची



परिचयः–

सीखने के प्रतिफल

किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर अपने दैनिक कक्षा–शिक्षण को संपादित करते है और कक्षा के अलावे अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं,उन्हें सीखने के प्रतिफल(learning outcome) कहते हैं।

सीखने के प्रतिफल, ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसका क्रियान्वयन अंततः शिक्षकों द्वारा ही करने की आवश्यकता है।

सीखने के प्रतिफल को छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से परे देखा जा सकता है। प्रतिफल एक बच्चे के विकास के अपेक्षाकृत संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चे की बढ़ोतरी का आकलन करते हैं। अतः, शिक्षक का ध्यान बच्चों का चरित्र निर्माण करना तथा ऐसे मूल्यों को रोपना होना चाहिए जिससे कि उनके सीखने की क्षमता में वृद्धि हो। शिक्षक बच्चों में वह आत्मविश्वास पैदा कर सके कि छात्र कल्पनाशील और सृजनशील बन सके। इस रूप में छात्रों का विकास ही उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें प्रतिस्पर्धा में उतारेगा।



सीखने की विशेषताएंः–

(i) व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है।
(ii) सीखना सतत् एवं जीवनपर्यंत चलनेवाली प्रक्रिया है।
(iii) सीखना (अधिगम) विकास की प्रक्रिया है।
(iv) सीखना (अधिगम) वातावरण की उपज है।
(v) सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है।
(vi) अधिगम, समायोजन की उपज है।
(vii) नवीन ज्ञान की खोज सीखना है।
(viii) अधिगम अनुभवों का संगठन है।
(ix) अधिगम सार्वभौमिक है।

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome)

बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा ?

विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई नए प्रयास किये जाते हैं। इन सबका उद्देश्य विद्यालयी छात्रों में शैक्षिक गुणवत्ता का विकास और अच्छी उपलब्धि स्तर को हासिल करना होता है।
किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के जो लक्ष्य या दक्षतायें निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के अलावे अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं:





सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में विद्यालय नेतृत्व की भूमिकाः–

★ विद्यालयों में शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा के आयोजन पर ही ध्यान देते हैं। पढ़ाई से बच्चे के मानसिक स्तर, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक ज्ञान में क्या सुधार हुआ, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किस कक्षा में शिक्षक बच्चे को किस तरह क्या–क्या पढ़ाएंगे और किस कक्षा में बच्चों को कितना ज्ञान होना चाहिए, यह निर्धारित किया गया है । विद्यालय नेतृत्व को यह ध्यान रखना चाहिए की विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा सीखने के प्रतिफल पर ध्यान में रखकर कक्षा में कार्य किया जा रहा है।

★ बच्चों के सीखने सम्बंधी प्रगति पर नजर बनाये रखने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यकता है की विद्यालय नेतृत्व बच्चों ने कक्षा में क्या सीखा, इसका ध्यान रखे।

★ विद्यालय नेतृत्व का यह दायित्व होना चाहिए की शिक्षक उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिगम प्रक्रियाओं को स्थानीय संदर्भ में पूर्णता तक करे ।

★ समय–समय पर बच्चों के वास्तविक स्तर का निर्धारण कर उनमें होने वाले परिवर्तन का मूल्यांकन भी आवश्यक हैं ।

★ पहली बार विद्यालय में आने वाला बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। बच्चे दुनियाँ के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसा वातावरण मिलना जरूरी है जहाँ वे बिना रोक–टोक के अपनी उत्सुकता के अनुसार अपने परीवेश की खोजबीन कर सकें। विद्यालय नेतृत्व की यह भूमिका होगी की विद्यालय का वातावरण ऐसा हो की बच्चे सीख सके ।



विद्यालय में पाठचर्या संबंधी अपेक्षाएँ

★ दूसरों की बातों को रुचि के साथ और ध्यान से सुनना।

★ अपने अनुभव–संसार और कल्पना – संसार को बेझिझक और सहज ढंग से आगेव्यक्त करना ।

★ अपनी भाषा में अपनी बात कहने, बात चीत करने की भरपूर आजादी और अवसर हो ।

★ स्तरानुसार विभिन्न प्रकार की विभिन्न भाषाओं में रोचक सामग्री, जैसे– बाल साहित्य, बाल पत्रिकाएँ पोस्टर ऑडियो विडियो सामग्री उपलब्ध हो।

★ बच्चों की उपस्थिति भी सीखने के प्रतिफल को प्रभावित करते हैं। बच्चे अगर विद्यालय में नियमित उपस्थित नहीं होंगे तो किसी भी विषय में उनकी समझ बेहतर नहीं हो सकेगी। अतः विद्यालय नेतृत्व को विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ।

★ नेतृत्वकर्ता एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो सहयोगी व मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करता है।

★ विद्यालय नेतृत्व द्वारा सम्मिलित होना चाहिए। कक्षा–कक्ष में अधिगम प्रक्रिया में विद्यालय नेतृत्व, शिक्षकों और विद्यार्थियों, दोनों के लिए सीखने का ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करेंजहाँ शिक्षक कार्य करने के नए तरीके आजमाए तथा नए कौशल विकसित करने को प्रोत्साहित हो।

★ अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ काम करते हुए, अपने विद्यालय के शिक्षण और सीखने की क्रिया में सुधार लाने पर अपना विचार साझा करें।



चरण 1

अपने विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन करना ।

उदाहरण के लिए, शिक्षक किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर रहे हैं ?

क्या विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं ?

चरण 2:

सुधार के लिए शिक्षण और सीखने की क्रिया का केन्द्र चुनना।

उदाहरण के लिए सभी कक्षाओं में समूह में कार्य कराना। बच्चों को स्तर के अनुसार सीखाना

★ शैक्षिणिक गतिविधियाँ/कार्यक्रम / FLN मुलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान/ज्ञानसेतु कार्यक्रम के विषय में खुद की एक अच्छी समझ और शिक्षकों को भी समझ विकसित करने में सहयोग देना।

विद्यालय में सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति के लिए विद्यालय नेतृत्व की भूमिकाः–

विद्यालय में सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति में विद्यालय नेतृत्व की अहम भूमिका है।

(i) अनुशासन का अनुपालन :–

विद्यालय नेतृत्व द्वारा सर्वप्रथम विद्यालय में अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुशासन, बच्चों में चरित्र निर्माण करते हैं तथा किसी भी सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है।





(ii) समय–सारणी का अनुपालनः–

विद्यालय का समय–सारणी बच्चों के सीखने के प्रतिफल को समाहित करता हो तथा

इसमें विभिन्न शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों का समायोजन हो तथा ससमय हो, इसे सुनिश्चित करना विद्यालय नेतृत्व का उतरदायित्व होना चाहिए।

(iii) प्रातः कालीन सभाः–

विद्यालय में होनेवाले प्रातः कालीन सभा/असेंबली बच्चों में सीखने के प्रतिफल को एक आयाम देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समावेश कर बच्चों की क्रियाशीलता तथा सृजन क्षमता का विकास करते हुए उनमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। इसमें होने वाले गतिविधियों का संबंध विद्यार्थियों में सीखने के प्रतिफल को बढ़ावा देने वाला हो जैसे– प्रार्थना के साथ समाचार वाचन, विचार व चिंतन, कविता पाठ, समसामयिक घटनाओं पर छोटी वैज्ञानिक जानकारी, भारत का संविधान इत्यादी का समावेश भी ससमय सुनिश्चित करना विद्यालय नेतृत्व का दायित्व है।





(iv) वर्ग कक्ष में अध्ययन तथा अध्यापनः–

कक्ष में अध्ययन तथा अध्यापन कार्य ससमय हो, इसे विद्यालय नेतृत्व के द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए।

(vi) शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारीः–

विद्यालय नेतृत्व को शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के बीच अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठतापूर्ण कार्यशैली का निर्माण करना।

(vii) पाठ–योजना का विद्यालय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षणः–

शिक्षकों द्वारा बनाए गए पाठ–योजना का विद्यालय नेतृत्व के द्वारा कम से कम एक कक्षा का प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाना चाहिए ताकि पाठ–योजना का समुचित क्रियान्वयन हो सके और सीखने के प्रतिफल में विद्यालय नेतृत्व के द्वारा शिक्षकों को आवश्यक तथा वांछित सहयोग करते हुए सीखने के प्रतिफल में बढ़ोतरी हो सके।

(viii) सहायक शिक्षकों के साथ शैक्षिक बैठक :–

विद्यालय नेतृत्व को सहायक शिक्षकों को समय–समय पर प्रोत्साहित करते हुए उनके कक्षा–कक्ष शिक्षण तथा विद्यालय सह शैक्षिक गतिविधियों में उचित तथा समुचित सहायता करते हुए उनमें क्षमता वृद्धि के लिए सहयोग करना चाहिए।

(ix) समुदाय तथा अभिभावकों को विद्यालय से जोड़नाः–

समय–समय पर शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन बच्चों के सीखने के प्रतिफल को प्रभावित करता है अभिभावकों को बच्चों के प्रर्दशन का पता चलता है तथा विद्यार्थियों को परिवार में शिक्षण वातावरण तैयार करने मे सहायता मिलती है।

समुदाय का परस्पर सहयोग भी विद्यालय में उचित वातावरण के निर्माण में सहायक होता है जिससे बच्चों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि होती है।





(x) सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजनः–

सीखने के प्रतिफल के रूप में सह शैक्षिक गतिविधियों का अहम भूमिका होती है।

जैसे– खेल, सांस्कृति कार्यक्रम, नाटक, लेखन, भाषण, शैक्षणिक भ्रमण इत्यादि।

(xi) उचित वातावरण का निर्माणः–

विद्यालय नेतृत्व की ये एक अन्य अहम भूमिका है कि विद्यालय में उचित वातावरण का निर्माण हो जहां शिक्षार्थी उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग एवं लाभ लेते हुए सीखने के प्रतिफल को प्राप्त कर सकें तथा शिक्षक इसमें अपना पूर्ण योगदान दे सकें।

(xi) स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकासः–

शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों में स्वस्थ और वैज्ञानिक का विकास करना भी विद्यालय नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। जिससे अलग–अलग परिवेश से आए शिक्षक/शिक्षार्थियों के आपसी मतभेद, विचार तथा दूरियों को पाटा जा सके और सीखने के प्रतिफल की ओर अग्रसर हो सकें।

(xiii) शिक्षकों,छात्र, छात्राओं की कार्यकुशलता में वृद्धिः–

विद्यालय नेतृत्व का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि विद्यालय में निरंतर शिक्षकों, छात्र तथा छात्राओं की कार्यकुशलता में वृद्धि पर कार्य करे।

(xiv) सहयोगात्मक कार्य शैली का निर्माणः–

विद्यालय परिसर में शिक्षार्थी, शिक्षक तथा विद्यालय नेतृत्व के बीच सहयोगात्मक ढंग से कार्य हो, ये सुनिश्चित करना भी विद्यालय नेतृत्व की जिम्मेदारी है।

★ विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों की सफलता तथा असफलता उसके शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षक ही केवल वह एक साधन है जो स्कूल को गतिशील बनाए रखता है। इसके बिना विद्यालय शून्य बना रहता है।

अतः, प्रधानाचार्य या विद्यालय नेतृत्व के द्वारा शिक्षकों को मार्ग–दर्शन व परामर्श देना ,उन्नति के अवसर प्रदान करना,कार्यभार संतुलित करना,सभी सुविधाएं देना तथा कार्य का मूल्यांकन कार्य करना चाहिए। ताकि विद्यालय का चहुंमुखी विकास किया जा सके। तभी शिक्षक ऊर्जावान रहकर पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ शिक्षार्थी के बहुमुखी विकास के लिए कार्य कर सकते हैं।

झारखंड में वर्तमान परिपेक्ष्य में सीखने के प्रतिफल में चुनौतियां और विद्यालय प्रमुख नेतृत्व का इसके समाधान में भूमिकाः–

लर्निंग गैप (learning gap) :–

वर्तमान समय में सीखने के प्रतिफल में एक मुख्य चुनौती बनकर हमारे समक्ष उभरा है।

लर्निंग गैप से अभिप्राय है कि एक विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार क्या सीखा और उसे कितना सीखना चाहिए का अंतर।

> लर्निंग गैप, विद्यार्थी के उम्र और उसको मिलने वाले अवसर पर निर्भर करता है। इस गैप को पाटने के लिए प्रधानाचार्य की अहम भूमिका होगी।

(i) विद्यालय में शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनाः–

बच्चों की उपस्थिति सीखने के प्रतिफल को वृहत रूप में प्रभावित करता है।

बच्चे यदि अनुपस्थित होते हैं तो सीखने में पिछड़ जाते हैं। अतः, विद्यालय नेतृत्व को शिक्षार्थियों के उपस्थिति को सुनिश्चित करना होगा।

(ii) ज्ञानसेतु कार्यक्रम / FLN कार्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयनः–

वर्तमान में विद्यालयों में चल रहे शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे ज्ञानसेतू तथा FLN कार्यक्रम का विद्यालयों में सही रूप से क्रियान्वयन विद्यालय नेतृत्व की जिम्मेदारी है।

ये कार्यक्रम बच्चों के लर्निंग गैप को पाटने तथा सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में सहायक हैं।



» इसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है की सबसे पहले प्रधानाचार्य/विद्यालय नेतृत्व इससे संबंधित पूरी

जानकारी रखे तभी सहयोगी शिक्षको को इसके सफल क्रियान्वयन में सहयोग दे सकते हैं।

» विद्यालय नेतृत्व इस बात को सुनिश्चित करे कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनो से शिक्षक बेस्ट प्रैक्टिस नवाचारों का नेतृत्व करते हुए सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें।

» ज्ञानसेतु के माध्यम से लर्निंग गैप को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा में पिछड़े बच्चों की नींव मजबूत कर उसे उसके वर्ग कक्ष के समकक्ष लाया जा सकता है।

» विद्यालय नेतृत्व की अहम भूमिका है कि विद्यालय के सभी शिक्षकों को ज्ञानसेतु तथा FLN की समुचित प्रशिक्षण तथा जानकारी मुहैया हो ताकि सभी शिक्षकों के द्वारा लर्निंग गैप को दूर करने तथा लर्निंग आउटकम की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

» प्रधानाचार्य विद्यालय नेतृत्व के द्वारा शिक्षकों को TLM का नियमित उपयोग कर कक्षा कक्ष को रुचिकर तथा विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा आनंददायी बनाते हुए सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

» समय–समय पर शिक्षक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स के द्वारा, सहयोगी शिक्षकों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण मुहैया कराना भी विद्यालय नेतृत्व का प्रयास होना चाहिए।

सीखने के प्रतिफल के सफल क्रियान्वयन में विद्यालय नेतृत्व के समक्ष कुछ चुनौतियांः–

★ विद्यालय में नामांकन के अनुसार शिक्षक का न होना।

★ विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, पानी की सुविधा,बिजली की सुविधा, कमरों का अभाव,शौचालय की सुविधा इत्यादि।

★ शिक्षकों को गैर – शैक्षणिक कार्यों में संलग्न रखना तथा विद्यालय से दूर रखना।

★ विद्यालयों (प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय) में शिक्षकेत्तर कर्मी का अभाव यथा क्लर्क, गार्ड,चपरासी, अकाउंटेंट इत्यादि के न होने से भी सीखने का प्रतिफल प्रभावित होता है।

इनकी कमी से विद्यालय नेतृत्व के द्वारा शिक्षण कार्य तथा सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति में अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपना पर्याप्त समय देने में असुविधा महसूस करते हैं।



सीखने के प्रतिफल में विद्यालय नेतृत्व के प्रभाव

(रॉबिन्सन एवं अन्य) 2008 के अनुसार

सीधा प्रभाव –

अध्यापकों का सहयोग एवं परामर्श करने के साथ–साथ स्वयं शिक्षण कार्य में संलग्न होना

विद्यालय नेतृत्व → विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल

मध्यस्थ प्रभाव –

अध्यापकों को अकादमिक सहयोग

अध्यापकों एवं अन्य हितधारकों के साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सहयोगात्मक कार्य ।

विद्यालय नेतृत्व → शिक्षक विकास → विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल

पारस्परिक प्रभाव –

स्वयं शिक्षण कार्य में संलग्न रहने के साथ–साथ अध्यापकों को उनके ज्ञान एवं कौशल को विस्तार देने में सहायता करता है।

प्रतिलोम प्रभाव –

बच्चों के आवश्यकताओं के अनुरुप शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना, विद्यालय में होने वाले क्रियाकलापों को बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं जैसे बच्चों की आर्थिक, समाजिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक स्थिति के अनुसार गतिविधियों का संचालन

student's participation and Learning in the school → **School Leadership**



झारखण्ड में बहुभाषिकता को शैक्षिक संसाधन बनाने में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका



श्रीमती बेतुल सुधर्म (प्र० प्रधानाध्यापिका रा० मध्य वि०, काँटाटोली, राँची)
श्रीमती रेजिस मेडलिन बाड़ा (स० शिक्षिका रा० मध्य विद्यालय, बरियातु, राँची)



"कोस–कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी"

प्रस्तावना

बहुभाषिकता झारखण्ड अस्मिता का अभिन्न अंग है। दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को बहुभाषी कहा जाता है। भाषायी विविधता भी बहुभाषिकता को परिभाषित करती है। झारखण्ड की बहुभाषिकता परिभाषित नहीं की जा सकती और उसको समझे बिना किसी भी साक्षरता, शिक्षा या सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है? झारखण्ड राज्य की बहुभाषिकता को समझना जरूरी है खासकर उन लोगों के लिए जो साक्षरता, शिक्षा, बौद्धिक विकास एवं सामाजिक बदलाव से जुड़े हैं।

साक्षरता कार्यक्रमों में शिक्षाकर्मी ये मान कर चलते हैं कि जो पढ़ा–लिखा नहीं है वो अज्ञानी है। पहली बात तो यह है कि जिसे पढ़ना–लिखना नहीं आता वह अज्ञानी नहीं है। वह पूरी तरह से अपनी भाषा या भाषाएँ समझ व बोल सकता है। उनमें कहानी व कविता कह सकता है। अपनी भाषा के साथ नये–नये प्रयोग कर सकता है। साक्षरता में जुटे शिक्षाकर्मी के सामने विद्यार्थी ज्ञान व भाषाओं की सम्पत्ति लिए बैठे हैं। इस भाषायी सम्पत्ति को संसाधन के रूप में बदलने में विद्यालयी नेतृत्व की अहम भूमिका होनी चाहिए जिससे इसका सदुपयोग कर साक्षरता सार्थक हो सके।

पूर्व में शिक्षाविदों की यह मान्यता थी कि बहुभाषिकता एवं बौद्धिक स्तर में विपरीतात्मक संबंध है अर्थात् बहुभाषिकता बढ़ती है तो बौद्धिक स्तर घटता है। लेकिन आज पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बहुभाषिकता व बौद्धिक स्तर में सीधा रिश्ता है–

जैसे–जैसे बहुभाषिकता बढ़ेगी बौद्धिक स्तर भी ऊँचा होगा।

झारखण्ड राज्य में 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं जिसकी जनसंख्या लगभग 192425 है, जो झारखण्ड की जनसंख्या में 0.72% है। इन 32 जनजातियों में से 8 आदिम जनजातियाँ हैं। अलग–अलग जनजातियों द्वारा अलग–अलग जनजातीय भाषाएँ बोली जाती हैं। झारखण्ड की भाषाएँ



झारखण्ड राज्य में जिलावार बोली जाने वाली भाषाएँ

जिला	जनजातीय भाषा
राँची	कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी
खूंटी	हो, भूमिज, मुंडारी, संथाली
सरायकेला	कुड़ुख, असुर
लातेहार	कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी
पलामु	कुड़ुख, असुर
गढ़वा	कुड़ुख
पाकुड़	संथाली, माल्तो
गोड्डा	संथाली, कुड़ुख, बिरहोर
रामगढ़	संथाली कुड़ुख, बिरहोर
चतरा	संथाली, कुड़ुख, बिरहोर, मुंडारी
प. सिंहभूम	हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुख
गुमला	कुड़ुख, खड़िया, असुर, बिरहोर
सिमडेगा	खड़िया, मुडारी, कुड़ुख
पू. सिंहभूम	हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुख, संथाली
कोडरमा	संथाली, कुरमाली, खोरठा
बोकारो	संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
धनबाद	संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा
गिरिडीह	संथाली, कुरमाली, खोरठा
देवघर	खोरठा, अंगिका
लोहरदगा	कुड़ुख, नागपुरी
दुमका	संथाली
जामताड़ा	संथाली
साहेबगंज	संथाली

शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ

1 छात्रों के संवाद कौशल में वृद्धि करती है। उनका भाषीय बोध उच्च होता है।

2 छात्रों की वैचारिक क्षमता का विकास होता है। प्राथमिक कक्षा–कक्ष में मातृभाषा का प्रयोग करने

से छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं।

3 भाषा के प्रति अनादर की भावना दूर होगी और वे दूसरी भाषा के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे।

भाषाओं की समरूपता व अंतरों को पहचानेंगे।

4 बहुभाषी बच्चों का भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और वे अकादमिक स्तर पर ज्यादा रचनात्मकता दिखाते हैं।

5 छात्रों के आत्म–सम्मान में वृद्धि होती है और वे विविध स्तर की परिस्थितियों से जूझने में कुशल हो जाते हैं।

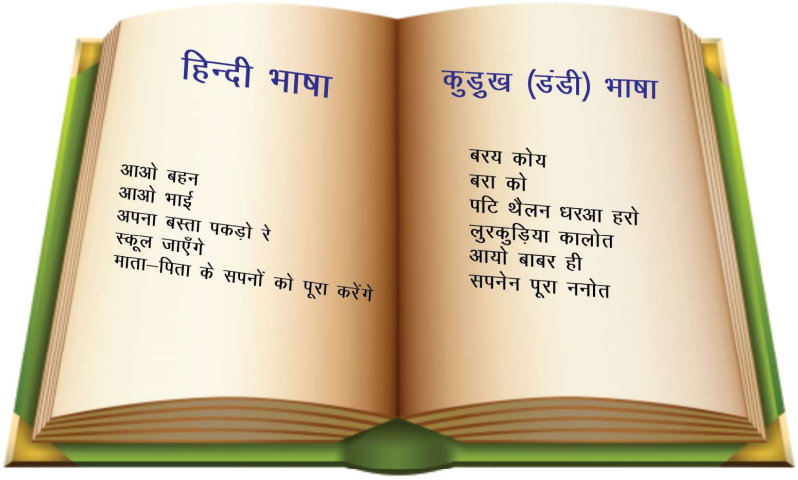
विद्यालय – नेतृत्व का बहुभाषिकता को संसाधन रूप में बदलने में योगदान

पठन – पाठन सामग्री में बदलाव

विद्यालय नेतृत्व द्वारा बच्चों को प्राथमिक स्तर की विधालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके। झारखण्ड सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। ऐसा करने से छात्रों को लगता है कि उनकी भाषा का भी पाठ्यक्रम में स्थान है।



प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में करने का कार्य प्रगति पर है। कुड़ुख, मुण्डारी, हो, संथाली एवं खड़िया भाषा में पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद के साथ पठन – पाठन सामग्री तैयार की जा चुकी है।



छात्रों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए तो वे मानकीकृत विद्यालयी भाषा खुद ही सीख जाएँगे। सभी बातों को वे आसानी से अपने माहौल से जोड़ पायेंगे।

पीयर ट्रांसलेटर की पहचानः–

विद्यालय नेतृत्व द्वारा बहुभाषीय कक्षा–कक्ष में से उन छात्रों की पहचान करनी होगी जो शिक्षक और छात्रों के बीच की कड़ी की भूमिका निभाएँगे। शिक्षक द्वारा बोली गयी भाषा को वह अनुवाद कर छात्रों को बताएगा एवं छात्रों की क्षेत्रीय भाषा को पुनः अनुवाद कर शिक्षकों को उनके समझ की जानकारी देंगे।

केस–स्टडीः–

मासी मारसल स्कूल, चरही, हजारीबाग, झारखण्ड की शिक्षिका रेजिस मेडलिन बाड़ा पहली कक्षा के छात्रों को पढ़ाया करती थीं जहाँ संथाली भाषा बच्चों की मातृभाषा थी। उन्हें पढ़ाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों की संथाली भाषा वो नहीं समझ पा रहीं थीं और उनकी हिन्दी भाषा बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान उन्हें उसी कक्षा में मिल गया। कक्षा में कुछ बच्चे हिन्दी और संथाली दोनों समझते थे। ये थे वो पीयर ट्रांसलेटर। इनकी मदद से शिक्षिका छात्रों से जुड़ पायीं। धीरे–धीरे सभी छात्र पीयर ट्रांसलेटर बनना चाहेंगे और नयी भाषा से जुड़ जाएँगे।



शिक्षिका छोटे–छोटे वाक्यों में बात किया करती थीं

संथाली वाक्य	हिन्दी वाक्य
अमा नुतूम चे कना?	(तुम्हारा नाम क्या है?)
अमा बाबा नुतूम चे कना?	(तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है?)
अमा आयो नुतूम चे कना?	(तुम्हारी माँ का नाम क्या है?)

जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में फिल्म का निर्माणः

क्षेत्रीय उपलब्धियों एवं समस्याओं से जुड़ी कहानियों पर आधारित छोटी–छोटी फिल्म बनायी जानी चाहिए। इन फिल्मों में अभिभावक, छात्र एवं शिक्षक अभिनय करेंगे। क्षेत्रीय भाषा में ही कहानियाँ कही जाएँगी। फिर उस फिल्म में विद्यालयी भाषा का सबटाइटल दिया जाएगा। बच्चे और अभिभावक जब फिल्म देखेंगे तो नयी भाषा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अभिभावक की विद्यालयी शिक्षण अधिगम में भागीदारी बढ़ेगी।

गीत, नृत्य, कविता, नाटक इत्यादि का बहुभाषा में सृजन –

विद्यालयी नेतृत्व का अहम योगदान सृजनकर्ता के रूप में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाये जाने के नवाचार में गीत, नृत्य, नाटक/कविता का समायोजन भी आवश्यक है। अतः छात्रों को उन्हीं की मातृभाषा में सृजित गीत, कविताओं इत्यादि के माध्यम से आकर्षित कर पढ़ाया जाना चाहिए। अलग–अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों की शब्दों के उच्चारण में विभिन्नता पाई जाती है जिसे इस नवाचार से दूर किया जा सकता है।

सादरी बालगीत

इने दड़ा बथेला उने दड़ा बथेला
दोयो दने बथेला
बेंगवा रे बैंगवा पानी बुलाई दे
खखड़ा रे खखड़ा माटी कोईड़
धमना रे धमना पाटा माइर दे
बकला रे बकला रोपा रोप दे

समृद्ध भाषायी परिवेश का निर्माण :–

विद्यालय नेतृत्व के मार्गदर्शन से एवं सहकर्मियों के सहयोग से विद्यालय में समृद्ध बहुभाषायी परिवेश का निर्माण करना होगा। सभी छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए। अलग–अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों पर कक्षा–परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से बचाना होगा। अन्यथा वे खामोश रहेंगे और विद्यालय से नहीं जुड़ना चाहेंगे। कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8 के बीच स्कूल से बाहर हो जाने वाले बच्चों की दर में वृद्धि हो सकती है।



विद्यार्थी अपनी मातृभाषा का उपयोग करके जोड़ों में किसी विषय की चर्चा करते हुए।

निष्कर्ष

झारखण्ड जैसे बहुभाषीय प्रदेश में एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान शिक्षण में काफी सहायक साबित हो सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारम्भिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है। एक से अधिक भाषाओं की जानकारी रखने वाला छात्र में सीखने–समझने की क्षमता अधिक होती है। वास्तव में बहुभाषायी परिवेश विद्यार्थियों में आत्म–सम्मान की वृद्धि करता है। भाषा के प्रति अनादर की भावना दूर होती है और वे दूसरी भाषा के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे। भाषाओं की समानता व अंतरों को पहचानेंगे तथा समाज में सहिष्णुता भी बढ़ेगी।

झारखंड में बाल–विवाह को रोकने में विद्यालय प्रधान की भूमिका



भात रंजन कुमार सिंह मॉडल स्कूल काँके, मेसरा राँची

बाल–विवाह क्या है ?

निर्धारित कानूनी उम्र से पहले होने वाला विवाह बाल विवाह है। लड़कों के मामले में यह उम्र 21 वर्ष है और लड़की के मामले में यह 18 वर्ष निर्धारित है। इस उम्र सीमा से कम उम्र में विवाह कानून की दृष्टि से अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसमें दोनों पक्ष– यानि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक या दोनों कम उम्र के हों।

इतिहास के पन्नों में

★ यह प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी। वैदिक युग में इसके संकेत नहीं मिलते है किंतु परवर्ती युगों में जब विदेशी आक्रमण होने लगे और बहु–बेटियों को सुरक्षित रखा जाना संभव नहीं होने लगा तब समाज में बाल–विवाह का प्रचलित होना माना जाता है। भारत में बाल विवाह को लड़कियों को विदेशी शासकों के बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाने लगा।

आधुनिक युग के आरंभ में राजा राम मोहन राय एवं केशव चंद्र सेन द्वारा इस विवाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कराने का बिल पास कराने से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि एक कुरीति के रूप में यह परंपरा समाज में गहरी पैठ बना चुकी थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे स्पेशल मैरेज एक्ट' कहा गया। इसके अंतर्गत शादी के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई एवं इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर भी सुधार न आने पर बाद में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास कराया गया जिसमें लड़कों की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़कियों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई।

स्वतंत्र भारत में भी सरकार द्वारा इसे रोकने के कई प्रयत्न किए गए और कई कानून बनाए गए जिससे कुछ हद तक इनमें सुधार आया परंतु यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। सरकार द्वारा इसके संबंध में कुछ कानून बनाए गए हैं जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो वर्तमान में अस्तित्व में है। यह अधिनियम बाल विवाह को आंशिक रूप से सीमित

करने के स्थान पर इसे सख्ती से प्रतिबंधित करता है। इस कानून के अंतर्गत, बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के दो साल के अंदर अपने बाल– विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं। किंतु यह कानून मुस्लिमों पर लागू नही होता यह इस कानून की सबसे बड़ी कमी है।

झारखण्ड की स्थिति

केंद्र सरकार की साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में 3 लाख 58 हजार 64 लोगों का बाल विवाह हुआ है जो कि पूरे देश के बाल विवाह का 3 प्रतिशत है। बाल विवाह के मामले में देशभर में झारखंड का 11वां स्थान है। यह आंकड़ा राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

झारखण्ड में बाल विवाह से ग्रसित वर्ग

झारखंड में बाल विवाह के मामले मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से में कमजोर एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में देखने को मिलता है। यह शहरों एवं गाँवों के लोगों में आम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों में बाल विवाह गहरे पैठ बनाए हुए है। ऐसे वर्गों में बाल विवाह का कारण अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रथाएँ. तथा रूढ़ियाँ, बच्चों के कम उम्र में खोने का डर इत्यादि हैं।

बाल विवाह के कारण

(i) लड़की को माता–पिता द्वारा अपने ऊपर बोझ समझना
(ii) शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव
(iii) रूढ़िवादिता से ग्रसित होना
(iv) अंधविश्वास
(v) निम्न आर्थिक स्थिति

दुष्परिणाम

बाल विवाह के दुष्परिणाम के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं–

विशेषकर लड़कियों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जैसे कि कम उम्र मे गर्भधारण करने और बच्चा जन्म देने के कारण हमेशा बीमार रहना

★ बच्चा दुबला–पतला और कमजोर होना
★ उच्च शिशु मृत्युदर
★ शिक्षा, परिवार एवं दोस्तों से अलगाव
★ यौन शोषण का शिकार होना

★ जीवन मे प्रगति के अवसरों को खो देना
★ बीच मे ही विद्यालय छोड़ देना
★ समाजिक भावनात्मक पहलू पर प्रभाव पड़ना
★ HIV जैसे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा

दाण्डिक विधान

भारत सरकार द्वारा लागू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत –

(i) बाल विवाह करवाने वाले या योगदान देने या बढ़ावा देने वाले व्यक्ति – वर एवं वधु पक्ष के माता–पिता, रिश्तेदार, बाराती 'विवाह करवाने वाले दण्ड के भागी बनेंगे

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

बाल विवाह को रोकने के लिए शिकायत कहाँ करे–

★ स्थानीय स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को इसके बारे में सूचित करें।
★ नजदीकी महिला थाना में लिखित शिकायत करें।
★ 1098 पर कॉल करके इसके बारे में बताएँ।
★ जिला में स्थित जिला बाल कल्याण समिति में शिकायत करें।
★ विद्यालय में मौजूद शिक्षक–शिक्षिकाओं को इसके बारे में बताएँ ।
★ क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं को सूचित करें।

मामलों को कम दर्ज किया जाना

बाल विवाह को रोकने में पुलिस में शिकायत के मामले में झारखंड के ऑकडे चौकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2019 मे तीन, वर्ष 2020 में तीन और वर्ष 2021 मे चार मामले ही बाल विवाह के दर्ज किए गए। उससे स्पष्ट है कि बाल विवाह के मामलों की पुलिस में शिकायत ही नहीं की जा रही है।

रोकथाम हेतु कानूनी पहलू

बाल विवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित कानूनी पहलू विचारणीय है–

(1) अनिवार्यतः FIR दर्ज करना,
(2) बाल विवाह को जुवेनाईल जस्टिस एक्ट तथा पोक्सो एक्ट से जोड़ना

(3) देश के हर जिले में बाल विवाह रोकने वाले अधिकारी की नियुक्ति की माँग

(4) अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के लिए उचित प्रशिक्षण देने तथा अभिभावकों को इसके खिलाफ प्रोत्साहन देना.

(5) विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों को जागरूक करना एवं जरूरत पड़ने पर स्वयं आगे आकर इसमें रोक लगाना।

व्यवहारिक पक्षः मामलों का विरोध

ऐसा नहीं है कि झारखण्ड में बाल–विवाह को रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे। झारखण्ड की बेटियों ने आगे आकर और हिम्मत दिखा कर अपने विरुद्ध होने वाले इस अपराध को रोकने की पहल की है।

गुमला की सुलेखा

गुमला जिले की 15 वर्षीय सुलेखा कुमारी की शादी उसके माता–पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध तय कर दी। लेकिन जैसे ही सुलेखा को इस बात की जानकारी मिली उसने इसका न केवल परिवार में विरोध किया, बल्कि जिला के बाल कल्याण समिति को लिखित शिकायत भी की।

कोडरमा की राधा

इसी प्रकार, 16 वर्ष की राधा पांडेय ने अपने परिवार का पुरजोर विरोध कर बाल विवाह रुकवाया। राधा के प्रयास को कोडरमा जिले के प्रशासन का साथ मिला।

कस्तूरबा विद्यालय की जागरूक बेटी

कस्तूरबा विद्यालय में नवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बहादुर बेटी तो बाल विवाह रुकवाने के लिए घर से भाग गई।

गिरिडीह जिले की चंपा

गरिडीह जिले की चंपा जो कि बाल मजदूर थी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के संपर्क में आकर न केवल विद्यालय आने को प्रेरित हुई अपितु उसने आधा दर्जन बाल विवाह रुकवाए। उसकी शोहरत ब्रिटेन तक पहुँची और उसे प्रतिष्ठित डायना अवार्ड भी दिया गया। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने चंपा को चेंज मेकर अवार्ड से भी सम्मानित किया। वर्तमान में चंपा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन की बाल महापंचायत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

मॉडल स्कूलः काँके राँची की पूजा

बाल विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें लड़के एवं लड़की की उम्र क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष से कम होती है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में देश भर में झारखण्ड राज्य अव्वल स्थान पर है और राजधानी राँची में इसका प्रतिशत 20.9 है।

मॉडल स्कूल काँके मेसरा जो कि शहर हेडक्वार्टर से महज 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है. के पोषक क्षेत्र में बाल विवाह एक आम घटना है। विगत चार–पाँच वर्षों में विद्यालय की दसवीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेने के पश्चात् कई बालिका ''की शादी कम उम्र में ही कर देने के सबूत बड़े आम हैं।

ऐसे ही मामलों में से एक विवाह में मेरे विद्यालय परिवार ने रोक लगाने में सफलता पाई है। हमलोग समय–समय पर बाल–विवाह विषयक जागरूकता रैली निकालते रहते हैं।

ऐसी ही एक सच्ची कहानी पूजा कुमारी की है। विद्यालय के वर्ग अष्टम में अध्ययनरत इस बालिका के विवाह कार्यक्रम की जानकारी विद्यालय परिवार को तब हुई 'जब उस बच्ची की सखी–सहेलियों ने कक्षा में चुपके–चुपके उसे चिढ़ाना शुरू किया। यह बात आग की तरह पूरे विद्यालय में फैल गई और शिक्षकों के कान तक जा पहुँची।

शिक्षकों को यह जानकर कोई ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि ऐसे कई और विवाह पोषक क्षेत्र में होने के खबर मिलते रहते थे फिर भी, विद्यालय के शिक्षक–शिक्षिकाओं ने इसे रोकने की ठान ली।



पहले तो हमने बच्ची को बुलाकर उससे इस बारे में पूछ–ताछ की और यह जानने की कोशिश की कि कम उम्र में विवाह का फैसला किसका है और क्या उसकी इसमें रजामंदी है ?

लड़की की बातों से पता चला कि वह अपने माता–पिता के निर्णय से बँधी हुई है और इसलिए वह बाध्य है। हालांकि उसने यह बात स्वीकार की कि शादी के बाद भी उसे पढ़ाई जारी रखना है और उसकी पढ़ाई पर वैवाहिक दायित्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बालिका से यह पूछे जाने पर कि उसके माता–पिता कम उम्र में ही क्यों उसका विवाह

कर देना चाहते हैं तो उसका जवाब था कि उसके इकलौते भाई की असामयिक मृत्यु के बाद वही एकमात्र अपने माता–पिता की जीवित संतान बची है और उसके माता–पिता इस कारण उसका विवाह कर देना चाहते हैं कि कहीं उसे भी कुछ हो न जाए !

इस स्थिति में मॉडल स्कूल के हम शिक्षकों ने उसके माता पिता की काउंसिलिंग कर विवाह को रोकवाना उचित नहीं समझा क्योंकि उनकी अजागरूकता हमे इस कार्य में असफल होने का डर पैदा कर रही थी।

तत्पश्चात् हमलोगों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की जिला इकाई से इस बारे में मदद माँगी। उन्होंने हमें जिला बाल कल्याण विभाग से संपर्क करने को कहा। हमलोगों के सूचना देते ही उक्त विभाग के लोग दूसरे ही दिन उस बालिका के घर जा पहुँचे जबकि वैवाहिक तैयारियाँ अपने जोरो पर थी।



जिला बाल कल्याण विभाग के अफसरों ने पहले तो उस बच्ची के माता–पिता को समझाने की कोशिश की लेकिन जब वे लोग नहीं माने तब वे उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठा कर जिला कार्यालय ले गए। वहाँ उनको बाल–विवाह से संबंधित विभिन्न दाण्डिक विधानों के बारे में बतलाया और कहा कि बाल विवाह के जुर्म में उन्हें भी दण्ड हो सकता है, वे तभी जा कर माने।



परंतु, माता–पिता का संदेह हम शिक्षकों पर बनने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अवश्य ही विद्यालय के शिक्षक– की उसमें भूमिका है और वे पर्दे के पीछे रह कर सारा खेल खेल रहे हैं। अगले ही दिन उस बच्ची की माँ विद्यालय पहुँच कर हो – हल्ला और हँगामा करने लगी। उसका कहना था कि मेरी इकलौती संतान है, वह भी यदि नहीं रहेंगी

तो मेरा वंश कैसे चलेगा! आप लोगों की बहन–बेटी होती तो भी क्या आप विवाह रोकवा देते! इत्यादि–इत्यादि।

हमलोगों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की। अपनी जान और आन बचाने हेतु झूठ भी बोला कि हमलोगों ने किसी को कोई खबर नहीं की है और न ही हम इस विवाह के बारे में जानकारी रखते हैं। इस प्रकार हमलोगों ने अपने डर और सफलता को काबू में रखा।

हम सब लोग विवाह रूकवा कर अंततः सफल हो गए थे और हमने इसे अपनी उपलब्धि माना किंतु यह खुशी कुछ ही समय तक रह पाई।

अगले ही वर्ष गुप–चुप तरीके से उसके परिजनों ने उस बच्ची की शादी कर दी और हम सफल होते. होते असफल रह गए।

वह बच्ची अभी हमारे विद्यालय में दसवीं कक्षा की छात्रा है और हम शिक्षक गण उसे और ऊँची कक्षाओं मे पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करते रहते हैं।

उद्‌बोधन गीत

अभी बचपन नहीं बीता, बच्ची के रिश्ते आ गए
अभी छुटपन नहीं बीता, शादी के किस्से छा गए
मेरे भाई, हम जीवन के एक हिस्से को खा गए।

जिस वक्त पढ़ना–लिखना और था खेलना–कूदना
बच्चे की शादी करके हम उसकी मासूमियत खा गए
मेरे भाई, हम जीवन के एक हिस्से को खा गए।

कभी भी ये न समझा उमर है कच्ची क्या जीते जी
उसे हम मार ही डालेंगे जिसकी होगी शादी
मेरे भाई, हम जीवन के एक हिस्से को खा गए।

हम उनके मन को न समझे बाँध दी बंधन उनमें
हम उनके तन को न समझे और दे दी क्रंदन उसमें
मेरे भाई, हम जीवन के एक हिस्से को खा गए।

उम्र से पहले ही हाथ पीले कर दी हमने
किया अपने ही हाथों, चूर उसके नन्हें सपने
मेरे भाई, हम जीवन के एक हिस्से को खा गए।





बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी :–

(1) बाल विवाह की रोकथाम में विद्यालय प्रधान की भूमिका है–

(क) नगण्य, (ख) महत्त्वपूर्ण,
(ग) प्रासंगिक (घ) (ख) एवं (ग) दोनों

(2.) स्पेशल मैरेज एक्ट के अंतर्गत लड़के एवं लड़की की विवाह आयु क्या निर्धारित थी ?

(क) क्रमशः 18 वर्ष एवं 14 वर्ष (ख) क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष
(ग) क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष (घ) क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष

(3) बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत वयस्कता प्राप्ति के कितने वर्ष के अंतर्गत कोई लड़का या लड़की अपने बाल– विवाह को अवैध घोषित करा सकता है ?

(क) चार वर्ष, (ख) तीन वर्ष.
(ग) दो वर्ष, (घ) एक वर्ष.

(4) वर्तमान में बाल विवाह हेतु निर्धारित न्यूनमम उम्र सीमा है–

(क) लड़का के लिए 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष
(ख) लड़का के लिए 18 वर्ष एवं लड़की के लिए 21 वर्ष
(ग) लड़का के लिए 18 वर्ष एवं लड़की के लिए 14 वर्ष
(घ) लड़का के लिए 14 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष

(5) बाल विवाह के दुष्परिणाम में शामिल हैं–

(क) उच्च मातृत्व मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर
(ख) ड्रॉप आउट की समस्या
(ग) स्वास्थ्य संबंधी बीमारी
(घ) उपरोक्त सभी

(6) किन दो महापुरुषों के प्रयास से भारत में बाल विवाह प्रतिबंधित हुआ?
(क) राम मोहन राय एवं हेनरी विवियन डिरोजियो
(ख) केशव चंद्र सेन एवं हेनरी विवियन डिरोजियो
(ग) राम मोहन राय एवं केशव चंद्र सेन
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं।

(7.) बाल विवाह के कारण हैं–

(क) लड़की को बोझ समझना (ख) शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव
(ग) निम्न आर्थिक स्थिति (घ) उपरोक्त सभी

(8.) बाल विवाह अधिकांशतः किस/किन वर्गों में देखा जाता है?

(क) सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग (ख) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
(ग) उपरोक्त दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

(9.) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन सजा का हकदार नहीं है ?

(क) वर–वधु के माता–पिता (ख) वर–वधु के रिश्तेदार
(ग) बाराती (घ) वर एवं वधु

(10) सुमेलित करें–

(अ) सुलेखा	(i) कोडरमा
(आ) राधा	(ii) गुमला
(इ) चंपा	(iii) राँची
(ई) पुजा	(iv) गिरिडीह

(अ)	(आ)	(इ)	(ई)	
(क)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(ख)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(ग)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(घ)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)

उत्तर– (1) – (घ) (6) – (ग)
(2) – (क) (7) – (घ)
(3) – (ग) (8) – (ग)
(4) – (क) (9) – (घ)
(5) – (घ) (10) – (ग)



झारखण्ड में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को विकसित करने में विद्यालय नेतृत्व की भूमिका :–



हिमांशु कुमार देव (प्रा०वि० गोपालपुर, जसीडीह,देवघर)

प्रस्तावना

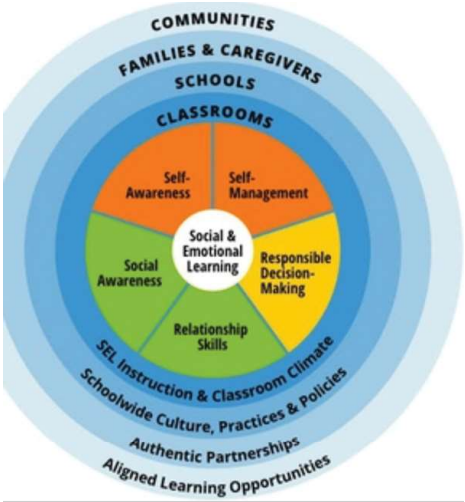
सामाजिक – भावनात्मक शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम के भीतर सामाजिक और भावनात्मक कौशल को बढ़ावा देना है। सामाजिक और भावनात्मक विकास का अर्थ है कि बच्चे कैसे समझना शुरू करते हैं कि वे कौन है वे क्या महसूस कर रहे हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते समय क्या उम्मीद करें। सामाजिक – भावनात्मक अधिगम बच्चों को सकारात्मक संबंधों को बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है यह बच्चे की भावनाओं का अनुभव, प्रबंधन और अभिव्यक्ति करने में सक्षम बनाता है।

सामाजिक भावनात्मक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे और वयस्क भावनाओं को समझने और उसी तरह से व्यक्त करने, सकारात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनको पूरा करने के लिए सक्षमता का विकास करते हैं स्वयं और दूसरों के लिए सहानुभूति विकसित करते हैं, सकारात्मक संबंध स्थापित करते है और बनाए रखते हैं।

जो विद्यालय नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय सामाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है–चूँकि बच्चे विद्यालय में अधिक समय तक रहते है। जो विद्यार्थीयों को अन्य सहपठियों के साथ अन्योन्यक्रिया करने का सुसंगठित ठाँचा प्रदान करता है। इसलिए विद्यालय को माता–पिता तथा परिवार की तुलना में बालक के समाजीकरण का आर्थिक अधिक महत्वपूर्ण कारक समझा जा रहा है।

परिचय के रूप में सामाजिक भावनात्मक अधिगम :–

सामाजिक भावनात्मक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे और समाज के लोगों को समझते है और उनका प्रबंधन करते हैं. साकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करते है जो दूसरों के लिए सहानभूती महसूस करते है एवं दर्शाते है।



गतिविधि 1.1 SEL को समझना

केस स्टडीज

स्थिति 1

संजय ने तीसरे स्तर तक अपने पड़ोस के एक स्कूल में पढ़ाई की। इस दौरान उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। स्कूल और घर पर उन्हें निचले दर्जे का समझ कर पढ़ाई करने के लिए कौशल नहीं होने'' वाले बच्चे के रूप में लेबल किया गया। एक प्रचलित पद्धति के अनुसार स्कूलों में जहां ''सर्वश्रेष्ठ'' प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाता है वहीं संजय को उसके प्रदर्शन के आधार पर कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठने के लिए वापस भेज दिया गया था। उन्हें ज्यादातर वयस्कों ने नजरअंदाज किया और अन्य बच्चों ने भी उन्हें भेदभाव के नजरिये से ही देखा। संजय याद करते हैं कि इस तरह के उपचार के साथ, ''मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था मैं हर समय घबरा जाता था।''

चर्चा के बिंदुः

1) प्रतिकूलता को पहचानें

क) माता–पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव
इ) माता–पिता ६ भाई–बहन की मृत्यु
ब) बुलीइंग यानि बदमाशी और नाम से पुकारना
र) सजा के रूप में शिक्षक की पिटाई

2) प्रतिकूलता का संजय पर क्या प्रभाव पड़ा?

क) देखभाल करने वाले वयस्कों के साथ कम या कोई बातचीत नहीं
ब) दूसरों के साथ बातचीत करने में आत्मविश्वास की कमी
इ) अध्ययन में दिलचस्पी की कमी
म) पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए रूचि का नहीं होना

3) संजय को क्या मदद मिलेगी?

क) सहानुभूति के साथ परामर्श करना
इ) बिना निर्णय के सुनना
ब) गलतियाँ करने और सीखने के लिए अवसर देना
र) तथ्य और मान्यताओं के आधार पर निर्णय लेना

स्थिति 2

रणजीत ने साझा किया तीसरी कक्षा में, हमसे वाक्य लिखने की उम्मीद थी, लेकिन जब मैं – अक्षरों को पहचानने में असमर्थ था, तो मैं कैसे वाक्य लिख सकता था ?'' । स्कूल के अधिकारियों से प्रतिक्रिया उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए नहीं थी, लेकिन शिक्षकों के सवालों के जवाब देने में असमर्थ होने की वजह से शिक्षकों से डांट पड़ती थी। उन्होंने फैसला किया कि सीखने में उनकी असमर्थता और शिक्षकों से रोजाना होने वाली दर्दनाक, आँखों में आंसू आने तक की डॉट के चलते अब यह ''स्कूल मेरे लिए नहीं है। जब उसने अपनी माँ को सूचित किया कि वह अपनी शिक्षा जारी नहीं रखेगा, तब उसके माता–पिता ने उसे बताया कि स्कूल नहीं जाना कोई विकल्प नहीं है।

चर्चा के बिंदु

प्रतिकूलता को पहचानें

(क) माता–पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव
इ) माता–पिता एवं भाई–बहन की मौत
ब) बदमाश के नाम से पुकारना
र) सजा के रूप में शिक्षक की डांट

रणजीत पर प्रतिकूलता का क्या प्रभाव पड़ा?

(क) देखभाल करने वाले वयस्कों के साथ कम या कोई बातचीत नहीं
(इ) दूसरों के साथ बातचीत करने में आत्मविश्वास की कमी
(ब) पढ़ाई के प्रति रुचि का अभाव
(र) पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए रुचि की कमी

(ब) रणजीत को कैसे मदद मिलेगी?

क) सहानुभूति के साथ परामर्श करना
इ) बिना निर्णय के सुनना
ब) गलतियाँ करने और सीखने के लिए अवसर देना
र) तथ्य और मान्यताओं के आधार पर निर्णय लेना

हमारे द्वारा बताये गए कुछ उदाहरणों के आधार पर क्या आप अपने अनुभव से कहानियाँ साझा कर सकते हैं? तीन उदाहरण साझा करें.

संक्षेप में –

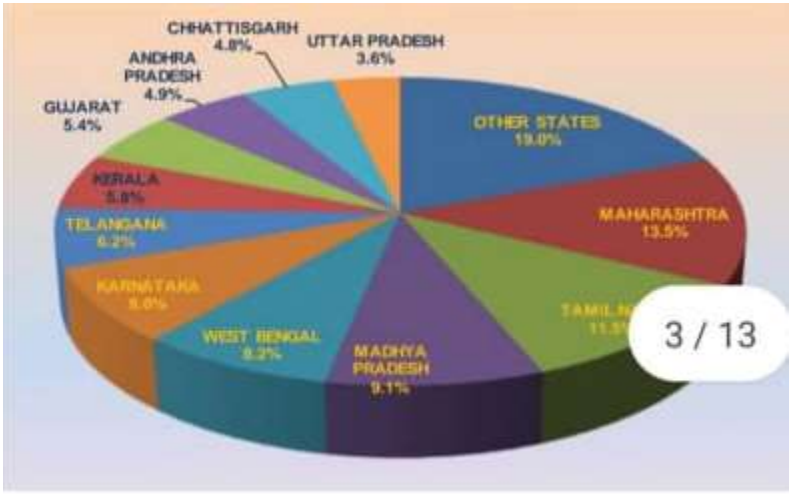
★ SEL प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बच्चे और वयस्क

★ SEL सोशल और इमोशनल वेल बीइंग (सामाजिक एवं भावनात्मक कल्याण) का एक तरीका है। हमने कक्षा के संदर्भ में SEL के कुछ अंशों को हल्के से छेड़ा है।

एस.ई.एल के बारे में अधिक जानने और सीखने के लिए कई संसाधन उपलब्ध है।

दुनिया भर में आत्महत्या
2019 में वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान के अनुसार

NCRB GOVERMENT OF INDIA REPORT के अनुसार भारत एवं उसके राज्यों में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा के आभाव में आत्महत्या करने वाले का आँकड़ा।





LIST-2.7

Incidence of Suicides in Mega-Cities, percentage share to All-India, rate of suicides and percentage change over previous year during 2018 – 2021

Year	Suicides in Cities	Cities Share to All India	Rate in Cities	% Variation over Previous Year (Incidence)
2018	21,408	15.9	13.3	0.8
2019	22,390	16.1	13.9	4.6
2020	23,855	15.6	14.8	6.5
2021	25,891	15.8	16.1	8.8

• As per data provided by States/UTs.

उपरोक्त आंकड़ों के अध्ययन के पश्च्यात झारखण्ड में सामाजिक भावनात्मक अधिगम विद्ययालय स्तर से नेतृत्व क्षमता विक्सित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम किये गए जिसके अंतर्गत प्रयास एवं प्रत्येक विद्यालय में बाल संसद गठन कराया गया ।

सामाजिक भावनात्मक अधिगम के लिए झारखण्ड राज्य के देवघर जिला अंतर्गत सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में विद्यालय नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए किए गये प्रयास :–

★ लागातार विद्यालय में बाल संसद की मदद से बच्चों उपस्थिति सुनिस्थित करना

★ प्रत्येक माह में PTA/PTM की बैठक में अभिभावक को विद्यालय से ना केवल सामाजिक भावनात्मक रूप से भी जोड़ने का प्रयोग किया गया ।

★ बच्चो की संख्या के अनुपात में बाल संसद और शिक्षको को प्रत्येक माह कार्य दायित्व देकर विद्यालय नेतृत्व क्षमता विकसित करने का प्रयास किया गया। NCF 2005 के अनुसार विद्यालय नेतृत्व क्षमता का विकसित करने हेतु कई प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

★ प्रत्येक बच्चों को एक निश्चित जिम्मेदारी देकर बाल–संसद, स्वच्छता मंत्री, अनुशासन मंत्री के साथ मिलकर किचन गार्डन, स्वच्छता अभियान विद्यालय में ग्रामीणों के सहयोग ते सामाजिक भावनात्मक अधिगम
विकसित किया गया।

★ विद्यालय चलो–चलें अभियान, गीत, स्वच्छता गीत, उससे संबंधित अन्य गतिविधियों भी सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहयोग किया ।

★ विद्यालय में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को आयोजित करने में क्षेत्रीय केन्द्र देवघर के उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के तहत गोद लिया जिनके सहयोग से कोविड 19 महामारी के समय में विद्यालय के बाहर गाँव के खलियान, गाँव के चबूतरे में क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सरोज कुमार मिश्र के सहयोग से श्री हिमांशु कुमार देव ने मोहल्ला कक्षा गाँव के युवाओं व ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया। जिससे विद्यालय की ओर ग्रामीणों का भावनात्मक जुडाव बढ़ने लगा । इसका परिणाम यहाँ बिजली की व्यवस्था व पानी की समुचित व्यवस्था हो गया। जिसका प्रतिफल यह हुआ कि विद्यालय को मंदिर के रूप में बच्चों के साथ–साथ ग्रामीणों मे भाव जगना प्रारंभ हुआ। जो विद्यालय नेतृत्व क्षमता यहाँ के बच्चों शिक्षकों एवं ग्रामीणों में सामाजिक व भावनात्मक के रूप में विकसित किया ।

★ विद्यालय चलो–चलें अभियान, गीत, स्वच्छता गीत, उससे संबंधित अन्य गतिविधियों भी सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहयोग किया।

★ विद्यालय में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को आयोजित करने में क्षेत्रीय केन्द्र देवघर के उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के तहत गोद लिया जिनके सहयोग से कोविड 19 महामारी के समय में विद्यालय के बाहर गाँव के खलियान, गाँव के चबूतरे में क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सरोज कुमार मिश्र के सहयोग से श्री हिमांशु कुमार देव ने मोहल्ला कक्षा गाँव के युवाओं व ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया। जिससे विद्यालय की ओर ग्रामीणों का भावनात्मक जुडाव बढ़ने लगा। इसका परिणाम यहाँ बिजली की व्यवस्था व पानी की समुचित व्यवस्था हो गया। जिसका प्रतिफल यह हुआ कि विद्यालय को मंदिर के रूप में बच्चों के साथ–साथ ग्रामीणों मे भाव जगना प्रारंभ हुआ। जो विद्यालय नेतृत्व क्षमता यहाँ के बच्चों शिक्षकों एवं ग्रामीणों में सामाजिक व भावनात्मक के रूप में विकसित किया।

"अच्छे नेता की पहचान यह है कि वह नेता तैयार करता है, अनुयायी नहीं"।

महात्मा गाँधी

विद्यालय नेतृत्व से अभिप्राय है– विद्यालय नेता के रूप में विद्यालय प्रमुख प्रधानाचार्य, शिक्षक, विधान संचालन में सहयोग करने वाले हर व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, जिसके अंतर्गत स्थानीय शैक्षिक एजेंसी या अन्य इकाई या अधिकारी है। बदलते परिवेश के अनुरूप भी समय के साथ अपडेट करने के लिए विद्यालय प्रमुखों की नेतृत्व का विकास किया जाना आवश्यक है। विद्यालय सामाजीकरण महत्वपूर्ण कारक है। चूँकि बच्चे विद्यालय में अधिक समय तक रहतें है जो बच्चों को उन्हें अपने शिक्षकों और सहपाठी के साथ अन्योन्यक्रिया करने का असंगठित दाँचा प्रदान करती है। इसलिए विद्यालय को माता–पिता तथा परिवार की तुलना में बालक के सामाजीकरण का अधिक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। शिक्षक बच्चों की क्षमता को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जिससे उनकी अपनी शैक्षणिक शिक्षा और भावनात्मक विकास को विनियमित करने में उन्हें सहयोग मिलता है। शिक्षक एक ऐसा इंजन है जो सामाजिक भावनाओं को सीखने और इसके अभ्यासों को स्कूलों और कक्षाओं दोनों में संचालित करता है। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा उन गुणों का विकास करता है जो आरम–जागरूकता और भावनात्मक

परिपक्वता में सुधार करते है।

शिक्षक वे इंजन है जो स्कूलों और कक्षाओं में मौजूदा परिस्थितियों में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम उनकी सामाजिक–भावनात्मक क्षमता के साथ–साथ विद्यालय नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सहयोग करती है। जिससे शिक्षक बच्चे के बीच मधुर एवं अच्छा संबंध समाज के लोगों के साथ ही साकारात्मक सामाजिक और भावनात्मक विकास का उद्‌भव होता है।

सामाजिक भावनात्मक शिक्षा के प्रमुख घटक भावनात्मक शिक्षा भी धारणा को पाँच पहलुओं में विभाजित करने में अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए सहयोगात्मक (CASEL) ने CASEL 5 रूपरेखा विकसित की, जो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा से संबंधित पाँच मौलिक कौशल या डोमेन की पहचान करती है।

आत्म जागरूकता– जागरूकता को आमतौर पर सामाजिक भावनात्मक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है यह अपनी स्वयं की भावनाओं, विकारों' और मूल्यों को पहचानने की क्षमता है, साथ ही वे विभिन्न स्थितियों में व्यवहार को कैसे प्रभावित करते है, जिसे झारखण्ड के विद्यालय में देखने को मिला।

स्व–प्रबंधन :–प्रबंधन एक धारणा है जिसका आरंभ जागरूकता से गहराई से जुडी हुई है और यह इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न तरीके से विकसित होती है। स्व–प्रबंधन व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न भावनाओं विचारों और व्यवहारों को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने की क्षमता करने की कामता को संदर्भित करता है, जिसे झारखण्ड के विद्यालय में देखा गया है

सामाजिक जागरूकता :– सामाजिक जागरूकता अगला कौशल क्षेत्र है जिसका संबंध सामाजिक शिक्षा से है। आत्म–जागरूकता के साथ इसकी तुलना करना, सोचने का एक अच्छा तरीका है। जबकि आत्म जागरुकता एक छात्र की कुछ को और उनकी गतिविधियों को समझने की क्षमता ले संबंधित है इसे घरातल पर झारखण्ड के विद्यालय में देखा गया है।

संबंध कौशल– संबंध कौशल सामाजिक – भावनात्मक शिक्षा से जुड़ा चौथा प्रमुख कौशल क्षेत्र है। संबंध कौशल को मोटे तौर पर दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता के साथ–साथ नकारात्मक सामाजिक प्रभावों से 'बचने के दौरान दूसरों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाता है इसका अनुप्रयोग झारखण्ड के विद्यालय में किया गया है ।

जिम्मेदार निर्णय लेना:– उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेना भावनात्मक विकास का अंतिम प्रमुख पहलू है सामाजिक रूप से इस कार्य को किसी के कार्यों के विभिन्न विकल्पों के प्रत्याशित परिणामों के प्रति जागरूक रहते हुए नैतिक, सुरक्षित, दयालुती और निर्णय लेने की समय के रूप में झारखण्ड के विद्यालय में अनुप्रयोग किया नेतृत्व क्षमता विकसित करने करने में सहायक हुआ है ।

सामाजिक भावनात्मक अधिगम की आवश्यकता :– सामाजिक भावनात्मक अधिगम के छात्रों को काफी लाभ होता है क्योंकि यह उन्हें आत्म–जागरुकता, एक अच्छी छवि विकसित करने गलतियों के लिए जवाबदेही लेने और दूसरों के साथ संबंध बनाने जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान विकसित करने में भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी सामाजिक

भावनात्मक शिक्षा के माध्यम में आवश्यक कौशल प्राप्त करते है, समस्या समाधान, भारी बाधाओं का सामना करना और उन प्रकार की आदतों को स्थापित करना चाहती है, जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए लड़ना, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, जिम्मेदारी लेना, उदाहरण से नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है इसका अनुप्रयोग झारखण्ड के विद्यालयों में किया गया है। जिसका प्रतिफल सकारात्मक रहा।

सामाजिक एवं भावनात्मक अधिगम का प्रतिफल

वैसे तो सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर, जसीडीह देवघर झारखण्ड का नाम केवल राज्य स्तरीय तक ही सीमित नहीं है बल्कि राज्य स्तर पर है। जहाँ राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक का पुरस्कार जीत चुका है जब इस विद्यालय में नए शिक्षक योगदान किए उसी समय से उनके ऊपर सामाजिक एवं मानसिक दबाव बना हुआ था कि यह विद्यालय राष्ट्रीय स्तर की रही है जहाँ के शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से लेकर विद्यालय को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार मिल चुका है जहाँ कार्य करना नए शिक्षक के लिए चुनौती से कम नहीं था क्योंकि यदि विद्यालय का किसी प्रकार के स्तर में शैक्षिक वातावरण में गिरावट होती तो शिक्षा विभाग से लेकर नए आने वाले शिक्षक की भी बदनामी होती।



कई सहकर्मी, कई शिक्षक व समाज के लागों से नए आने वाले शिक्षक को ताने भी सुनने को मिलता था। लेकिन नए शिक्षक अपने कर्म के प्रति अडिग थे। शायद विपरीत परिस्थितियों में काम करने का तजुरबा ही कुछ और होता है। नाम का तो नए शिक्षक को राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय मिला था लेकिन संसाधनों व सहयोगात्मक लागों की कमी नए शिक्षक को झेलनी पड़ रही थी। ग्रामीण परिवेश प्रकृति की गोद में बसा विद्यालय काफी सुंदर दिखता है लेकिन इस विद्यालय में बिजली और पानी की दिक्कत थी। जैसे ही नए शिक्षक अपने तौर तरीके से तत्कालीन विद्यालय में कार्य करना प्रारंभ किया संसाधनों और समुदाय के लोगों के सहयोग की कमियाँ नजर आने लगीं जिसे दूर करने के लिए शिक्षक ने योजना बनाई जिसके अनुरूप कार्य करना प्रारंभ किया। तभी अचानक गोपालपुर गाँव के नाम को सार्थक करने वाले परिवार से भेंट हुई। जिनके बारे में पहले सुना करते थे लेकिन कभी मिला नहीं था जिनका नाम श्री गोपाल सिंह, जिनके पूरे परिवार के सहयोग से हमारे विद्यालय को बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की नई जिनके बदौलत मेरे अंदर तत्कालीन विद्यालय में कार्य करने की ऊर्जा संचालित हुई धीरे–धीरे यहाँ के लोगों विद्यालय परिवार से समन्वय स्थापित करना प्रारंभ किया जिससे शिक्षक वातावरण गतिविधि आधारित शिक्षा निजी विद्यालय के बच्चों का नाम कटवाकर इस विद्यालय में 20 बच्चे नामांकन किया गया जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।









धीरे–धीरे विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनना तैयार हुआ जहाँ कविता आधारित गतिविधियाँ, विद्यालय चलो अभियान, स्वच्छता संबंधी अभियान, शिक्षक अभिभावक की बैठक, महापुरूषों की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना, खेल–कूद प्रतियोगिता, पेंटिंग इत्यादि में बेहतर करने वाले बच्चों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों के प्रोत्साहन हेंतु किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के हाथों अभिभावक के सामने पुरस्कृत करने से समाज, विद्यालय शिक्षकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने में सहयोग मिला जो मील का पत्थर साबित हुआ तभी कोरोना महामारी का प्रकोप हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। विद्यालय बंद होने के बाद ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रयास किया गया लेकिन सभी बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा प्रयास सफल प्रतीत नहीं हो रहा था तभी उन्नत भारत अभियान के तहत इग्नू राष्ट्रीय केंद्र देवघर झारखण्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉ0 सरोज कुमार मिश्र के सहयोग से इस विद्यालय को गोद लिया गया।







जिनके अथक प्रयास से विद्यालय में अध्ययनरत समुदायिक सहयोग – से विद्यालय को बेहतर रूप से तैयार करने हेतु समुदाय का सहयोग लेना प्रारंभ किया जिसके लिए समुदाय के प्रत्येक घरों तक स्वयं जाकर नामांकन अभियान से लेकर विद्यालय के सभी कार्यों में भागीदारी लेने हेतु प्रेरित किया जो इस विद्यालय के लिए वरदान साबित हुआ।













स्वच्छता अभियान के तहत समुदाय के सभी लोग अपने हाथ में झाड़ू इत्यादि ले कर विद्यालय प्रांगण से शौचालय तक के साफ सफाई एवं विद्यालय को सुदर बनाए रखने के लिए आगे बढ़े। स्वच्छता मंत्री वरूण कुमार एवं आँचल के नेतृत्व में विद्यालय प्रांगण के चारों ओर पेड़–पौधे एवं किचन गार्डन लगाया गया जिसकी सराहना राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय टीम ने किया।



स्वर्णिम वर्ष –बाबा बैद्यनाथ की कृपा से 3 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के हाथों स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के रूप मे एक लाख रूपये, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस्से इस अंदर की कार्य करने की ऊर्जा को और तेज कर दिया तथा लगातार कार्य करते रहे।



जो विद्यालय नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय सामाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है–चूँकि बच्चे विद्यालय में लंबा समय व्यतीत करते हैं जो बच्चों को उन्हें अपने शिक्षकों और समकक्षियों के साथ अन्योन्यक्रिया करने का सुसंगठित ढ़ाँचा प्रदान करता है। इसलिए विद्यालय को माता–पिता तथा परिवार की तुलना में बालक के सामाजीकरण कों अधिक महत्वपूर्ण कारक समझा जा रहा है।

Modules Development Member's



डॉ.डी.एन. सिंह



डॉ.निरूपमा कुमारी



डॉ.शाहनवाज कुरैशी



सुप्रिया कुमारी



अमाद उद्दीन रागिब



अंजनी आनंद



भूपेश प्रसाद श्रीवास्तव



प्रभात रंजन कुमार



हिमांशु कुमार देव



बेतुल सुधर्म



रेजिस मेडलिन



तारा कुमारी



मोनिका प्रसाद

Jharkhand Concil of Educational Research and Traininig, Ranchi
D.I.E.T Campus, Ratu, Ranchi-835255, email:jcert.ran@gmail.com